● वर्ष-5

● अंक-201

रायपुर, गुरुवार
09 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› वनोपज आधारित रोजगार को दें...

मोदी कैबिनेट में लिये गये बड़े फैसले

राजस्थान को रिफाइनरी और मेट्रो की सौगात

नईदिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे प्रमुख निर्णयों में राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड़ परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र पर पडेगा। इन फैसलों में राजस्थान में विशाल रिफाइनरी परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, जयपुर मेट्रो विस्तार और किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी से जुड़े निर्णय शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे प्रमुख निर्णयों में राजस्थान के बालोतरा

जिले के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड़ परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की लागत अब बढ़ाकर लगभग उन्यासी हजार चार सौ उनसठ करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे कुल निवेश उन्नीस हजार छह सौ करोड़ रुपये हो जाएगा। यह रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और इसमें पेट्रोल, डीजल के साथ साथ पॉलीप्रोपिलीन, एलएलडीपीई, एचडीपीई तथा बेंजीन जैसे पेट्रो रसायन उत्पाद तैयार किए जाएंगे। यह परियोजना देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस रिफाइनरी परियोजना से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण के दौरान लगभग पच्चीस हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है और भविष्य में भी रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना की वाणिज्यिक शुरुआत एक जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन को मजबूत करने के लिए भी दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहली परियोजना कालई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता बारह सौ मेगावाट होगी और इस पर लगभग चौदह हजार एक सौ पांच करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना लोहित नदी पर बनेगी और इससे हर साल चार हजार आठ सौ बावन मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना से राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन में भी मदद मिलेगी।

दूसरी प्रमुख परियोजना कमला जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता सत्रह सौ बीस मेगावाट होगी और इस पर लगभग छब्बीस हजार उनहत्तर करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से हर साल छह हजार आठ सौ सत्तर मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के तहत सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण होगा।

अब बड़े मामलों की सुनवाई केवल सीजेआई ही करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने बदला नियम

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। नए नियम के तहत अब अत्यंत आवश्यक मामले, जिनमें नियमित सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता, उनका उल्लेख केवल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही किया जा सकेगा। यह नियम तब भी प्रभावी रहेगा जब मुख्य न्यायाधीश किसी संविधान पीठ की अध्यक्षता करने में व्यस्त हों। न्यायालय के इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता लाना और तत्काल सुनवाई के मामलों के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

छह अप्रैल को जारी आधिकारिक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अत्यंत आवश्यक मामलों का उल्लेख अब केवल अदालत संख्या-1 (मुख्य न्यायाधीश की अदालत) के समक्ष ही करने की अनुमति है। परिपत्र में जोर देकर कहा गया है कि भले ही प्रधान

न्यायाधीश किसी भी विशेष पीठ या संविधान पीठ का हिस्सा हों, वकीलों को ऐसे मामलों के लिए किसी अन्य पीठ के सामने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्देश 29 नवंबर, 2025 के पिछले परिपत्र के संदर्भ में जारी किया गया है, ताकि सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी भ्रम को दूर किया जा सके। बता दें कि इस प्रशासनिक बदलाव के बीच, मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में न्यायिक बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी अपने विचार साझा किए थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि देश भर में न्यायिक परिसरों का विस्तार हो रहा है और सभी राज्य सरकारें अब यह स्वीकार कर रही हैं कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक कार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान निर्माताओं का न्याय तक पहुंच के सिद्धांत में अटूट विश्वास था, और प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना इसी संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, यह केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि भारतीय गणतंत्र की एक गंभीर प्रतिबद्धता है।इससे पहले की व्यवस्था के अनुसार, यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते थे या किसी संविधान पीठ की सुनवाई में व्यस्त रहते थे, तो अत्यावश्यक मामलों के उल्लेख के लिए उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज (सीनियर मोस्ट जज) के पास जाने का प्रावधान था। वकीलों को तत्काल राहत पाने के लिए वरिष्ठ जजों की पीठ के सामने अपनी अर्जी रखने की अनुमति थी। हालांकि, नए सर्कुलर ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह मुख्य न्यायाधीश की पीठ तक ही सीमित कर दिया है।

आरएसएस चीफ मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव और आध्यात्मिक गुरु राजेंद्र दास वृंदावन स्थित श्री मलूक पीठ में श्री मलूक जयंती महोत्सव में शामिल हुए।

असम, केरल और पुडुचेरी में आज मतदान

करोड़ों मतदाता, हजारों उम्मीदवार और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान

नई दिल्ली। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत 9 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगी। इन सभी सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी की जाएगी।

असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह से केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं, पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से पांच सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। यहां कुल 9.44 लाख मतदाता हैं, जिनमें लगभग 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं।

असम में व्यापक सुरक्षा

असम चुनाव के लिए 31,490 पोलिंग स्टेशनों पर 25,054,463 मतदाता मताधिकार के हकदार हैं और इन सभी मतदान केंद्रों की निगरानी लाइव वेबकास्ट के ज़रिए की जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से जारी जानकारी में कहा गया है कि सीईओ अनुराग गोयल की अगुवाई में सभी संबंधित अधिकारी मतदान प्रक्रिया से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियां देख रहे हैं। कानून-व्यवस्था और चुनाव खर्च समेत सभी पहलुओं की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया है। निगरानी व्यवस्था और मज़बूत करने के लिए आयोग के निर्देशों के मुताबिक वेबकास्टिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

सभी 31,490 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की सुविधाएं चालू कर दी गई हैं, इनमें 31,486 मुख्य मतदान केंद्र और 4 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।

प्रमुख समाचार

लोकतंत्र का गला घोंट रहा सत्ता पक्षः अभिषेक मनु सिंघवी

नई दिल्ली। देश में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के नोटिस के बाद भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस को लेकर सभी विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी जमकर आलोचना हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे गंभीर मामला है बताते हुए

कहा कि सत्ता पक्ष चुनाव आयोग से क्यों घबरा रहा है? सत्ता पक्ष हर चीज को क्यों झुठलाने का प्रयास करता है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र का गला घोंटने का काम करता है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया अब केवल एक व्यक्ति के निर्णय तक सिमट कर रह गई है। महाभियोग जैसी गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया को किसी एक व्यक्ति के विवेक पर छोड़ देना खतरनाक है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र के मंदिर , सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी न्यायिक निकाय और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के साथ होने वाले सलाह के माध्यम से होने वाली भविष्य की किसी भी जांच या बारीकी से परखने की संभावना को ही खत्म कर देता है।

पश्चिम बंगाल में फिर बनेगी ममता सरकारः अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भाजपा को जनता करारा जवाब देगी।पत्रकारों से

बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश, बेईमानी या साजिश कर ले, पश्चिम बंगाल की जनता उसे सत्ता में नहीं आने देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनता का समर्थन बना हुआ है और यही चुनाव परिणामों में भी दिखाई देगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग का ध्यान मतदाताओं को जोड़ने के बजाय उन्हें हटाने पर केंद्रित दिखाई देता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।

पिनाराई विजयन पर बरसे रेवंत रेड्डी

तिरुवनंतपुरम। केरलम में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच शुरू हुआ विकास का विवाद अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बहस चल रही है। अब रेवंत रेड्डी ने एक पत्र

लिखकर केरल के विकास मॉडल पर सवाल उठाए हैं। दरअसल रेवंत रेड्डी ने केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को चुनौती दी थी कि वो तेलंगाना आकर देखें कि उनकी सरकार ने चुनावी वादों को कैसे पूरा किया है। इसके जवाब में पिनाराई विजयन ने भी बताया था कि केरल में कौन-कौन सी योजनाएं बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। अब रेवंत रेड्डी ने इस जवाब पर पलटवार किया है और एक पत्र लिखा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस पत्र में उन्होंने पिनाराई विजयन की तरफ से जारी किए दए केरल के आंकड़ों को पुराना बताया है। रेवंत रेड्डी ने अपने पत्र में लिखा कि पिनाराई विजयन 120 महीनों से सत्ता में हैं, जबकि तेलंगाना की सरकार ने सिर्फ 28 महीनों में बड़े बदलाव किए हैं।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की 39 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लेते हुए ईडी ने उनका एक घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट को कुर्क किया है. इन सभी संपत्तियों की कीमत 39 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. सूत्रों की मानें तो ईडी ने क्प्रिवेंशन

ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टक्र के तहत जवाद अहमद की संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है. इसके तहत ईडी ने जवाद अहमद की कुल 39.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. जब्त की गई संपत्तियों में दिल्ली के जामिया नगर का एक मकान और फरीदाबाद के धौज इलाके की कृषि भूमि शामिल है। इसके अलावा, बैंक खातों में जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी रोक लगा दी गई है. बता दें कि जवाद अहमद सिद्दीकी फिलहाल जेल में हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने शिक्षण संस्थानों की मान्यता और पहचान के बारे में गलत जानकारी देकर छात्रों को धोखा दिया है। सिद्दीकी को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था।

बंगाल में 90 लाख वोटर्स हटे ईसी ने जारी किया डेटा

नईदिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल स्क्रूक में विचाराधीन 60 लाख से अधिक मामलों का विस्तृत डेटा जारी कर दिया है इस प्रक्रिया में अब तक कुल 9066 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं आयोग ने पहली बार जिलेवार तरीके से नाम जोड़ने और हटाने की जानकारी भी साझा की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है बंगाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया तीन बड़े चरणों में पूरी हुई है दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तब 582 लाख नाम हटाए गए थे इसके बाद फरवरी 2026 में अंतिम सूची के प्रकाशन तक 546 लाख और नाम हटाए गए वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से अधिक नामों को हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे कुल संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है आयोग के मुताबिक, चुनाव आयोग ने क्लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीक्र यानी डेटा में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं को जांच के दायरे में रखा था इन मामलों को क्रअंडर एडजुडिकेशनक्र कैटेगरी में रखा गया था,ताकि न्यायिक अधिकारी इनकी जांच कर सकें अब तक लगभग 5984 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है ।

सत्ता ही नहीं, साख की भी लड़ाईहै केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव आज

शेखर अय्यर

केरल में 81 वर्षीय पिनाराई विजयन अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचते हैं, तो वह देश में मार्क्सवादी पार्टी की एकमात्र सरकार को बचा सकेंगे। हालांकि, उनके नेतृत्व में, सत्ताधारी वामपंथी दल पिछले साल के स्थानीय निकाय चुनावों में फीके प्रदर्शन के बाद अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष ही कर रहा है। केरल को कम्युनिस्टों का आखिरी गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2018 में त्रिपुरा में सत्ता गंवाने और 2011 में अपने पुराने गढ़ पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हाशिये पर चले जाने (एक भी विधायक न होने) के बाद यही एकमात्र राज्य बचा है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, जबकि भाजपा भी राज्य में तीसरी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है।

विजयन की मुश्किलों के तार खुद उनकी पार्टी सीपीआई (एम) के भीतर ही देखे जा सकते हैं। कई मार्क्सवादी दिग्गज उनके काम करने के तरीके से नाखुश हैं और उन पर वामपंथ के 'मूल सिद्धांतों' को कमजोर करने व पिछले दस वर्षों में व्यापार और व्यवसायों के प्रति अधिक मित्रवत होने का आरोप लगाते हैं। उन पर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर झुकाव का आरोप भी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का उनकी सरकार द्वारा समर्थन किए जाने से वामपंथी दल को हिंदू मतदाताओं का नुकसान उठाना पड़ा है, जो राज्य की आबादी का लगभग 54.73 प्रतिशत हैं। अब, अपने पहले के रुख में बदलाव के चलते विजयन हिंदू समर्थक समूहों की बहुत अधिक आलोचना नहीं कर रहे हैं।

विजयन अपने चुनावी अभियान में साफ तौर पर 'विकास' (विकासनम) को ही सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में केरल ने कई कठिन दौरों का मजबूती से सामना किया है-चाहे वह 2018 की विनाशकारी बाढ़ हो या कोविड महामारी का दौर। साथ ही, उन्होंने पूरे राज्य में बड़ा आर्थिक बदलाव लाया है और कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिये गरीब तबके का भी ख्याल रखा है। वहीं, कांग्रेस ईसाइयों के बीच अपने मजबूत आधार पर दांव लगा रही है, जिनकी आबादी में हिस्सेदारी 18.38 प्रतिशत है। साथ ही, राहुल गांधी के जोरदार चुनावी प्रचार के चलते कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता, जो करीब 26.56 प्रतिशत हैं, इस बार वामपंथियों से दूरी बनाकर यूडीएफ के साथ आएंगे, क्योंकि यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) एक अहम साझीदार है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यह होगी कि राज्य के हिंदू मतदाता एकजुट होकर उसके पक्ष में वोट करें। अगर ऐसा होता है, तो भाजपा इतनी सीटें हासिल कर सकती है कि वह सत्ताधारी एलडीएफ और पिनाराई विजयन के सामने मजबूती से उभर सके। हालांकि, इसकी संभावना कम ही है, फिर भी, भाजपा केरल में ईसाई समुदाय के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क बना रही है। उसने बीडीजेएस, ट्वेंटी-20 पार्टी, केरल कांग्रेस (डेमोक्रेटिक), केरल कामराज कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पक्का कर लिया है।

असम में, हिमंत बिस्वा सरमा को पूरा भरोसा है कि वह भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाएंगे और खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक आधार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस का संगठन राहुल गांधी की उस पसंद के कारण लड़खड़ा गया है, जिसमें उन्होंने एकमात्र गौरव गोगोई को ही असम में पार्टी की किस्मत का फैसला करने वाला बना दिया था। असम में अवैध प्रवासन ने वहां की मूल गैर-मुस्लिम आबादी के मन में गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं।

मुख्यमंत्री के तौर पर, हिमंत ने जमीनी स्तर पर कई मोर्चों पर विकास करके अपना काम बखूबी निभाया है। इनमें कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं को नकद आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। कांग्रेस पिछले एक दशक से विपक्ष में है, जबकि भाजपा लगातार दो बार सत्ता का सुख भोग चुकी है। चुनावी चर्चा एक बार फिर जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठिये जैसे वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित हो गई है और कांग्रेस असम के बहुसंख्यक लोगों की चिंताओं को समझने में नाकाम रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 93 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। यही नहीं, 2014 के बाद से भाजपा ने असम में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं हारा है। ऐसे में, मौजूदा माहौल को देखते हुए पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की मजबूत दावेदार नजर आ रही है।

लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण-कलेक्टर

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को साप्ताहिक समय -सीमा की बैठक में राज्य और केंद्र शासन की.विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भूमिगत जल के रिचार्ज हेतु सभी शासकीय भवनों में सोखता गड्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएँ निर्मित करने और जन भागीदारी से जल संचयन के कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नहरों के आसपास भी ऐसी संरचनाएं निर्मित करें जो पानी रोककर भूमिगत जल रिचार्ज में सहायक हों।उन्होंने खेतों के सबसे निचले क्षेत्र में भी जल संरक्षण की संरचना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने आंगनवाड़ी,शासकीय और निजी स्कूलों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता पिट निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में जन जागरूकता हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रस्ताव के साथ आम नागरिकों से इस कार्य में सहयोग की अपील भी की है । जल संचयन की संरचनाओं के गुणवत्ता पूर्ण निर्माण में बाद उसकी फोटो और अनिवार्य जियो टैगिंग के भी निर्देश उन्होंने दिए।

बैठक में उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत विभिन्न प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण और पोर्टल में तत्काल एंट्री के निर्देश भी दिए हैं,ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी -कर्मचारी पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

उन्होंने राजस्व पखवाड़े में पटवारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण करने को कहा है। श्री शर्मा ने जनगणना के कार्यों को संवेदनशीलता और कर्मठता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा जनगणना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने भूराजस्व संहिता के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन नागरिकों को भी लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पंचायत स्तर पर आबादी भूमि का चिन्हांकन कर भूमिहीनों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।

उप पंजीयक सहकारी समिति ने 25 धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को जारी किया नोटिस

■ **सहकारी विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि जांजगीर चांपा जिला धान उठाव में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है.**

जांजगीर चांपा। उप पंजीयक सहकारी समिति ने जिले के 25 धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी किया है। 3 दिन के अंदर समिति द्वारा धान जमा करने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार ने इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की थी। जांजगीर चांपा जिले में 1लाख 18 हजार किसानो ने 129 धान खरीदी केंद्रों के जरिए 6 लाख मीट्रिक टन धान बेचा। जिसके बाद सहकारी विभाग ने मिलर्स के माध्यम से धान उठाव की प्रक्रिया पूरी की। अब तक 105 धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव कर जीरो शॉर्टेज कर दिया गया है। जिले के 25 धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव पूरा नहीं हो पाया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी किसी भी स्थिति मे धान को जमा करवाने मे जुटे हैं, 3 दिन के अंदर बचे हुए धान को उठाव कराने में निर्देश दिए है। जांजगीर चांपा जिले में कुल 6 लाख 16 हजार 764 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 6 लाख 15 हजार 596 मीट्रिक टन धान जमा करा दिया गया है। 25 केन्द्रों में से 11 हजार 674 क्विंटल धान जमा करना बाकि है, जिसमे कड़ारी और बक्सरा धान खरीदी केंद्र में 2 हजार क्विंटल से ज्यादा धान बकाया है, इसके अलावा 23 समितियों में बचा धान सैकड़ा और दहाई के अंक में ही है।

फॉग मशीन मॉडल' से जंगल सुरक्षित डीएफओ ने खुद थामी मशीन

■ **आगजनी की घटनाओं में आई 80 फीसदी की कमी**

महासमुंद। गर्मियों के मौसम में हर साल बढ़ने वाली आगजनी की घटनाओं पर इस बार महासमुंद वन विभाग ने प्रभावी नियंत्रण पा लिया है। खेतों में पराली जलाने या झाड़ियों में लगाई गई आग अक्सर जंगलों तक पहुंचकर भारी नुकसान करती थी, लेकिन इस बार विभाग की नई रणनीति और जमीनी सक्रियता से हालात बदलते नजर आ रहे हैं।

इस अभियान की अगुवाई कर रहे डीएफओ मयंक पांडेय खुद मैदान में उतरकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे अपनी गाड़ी में फॉग मशीन रखते हैं, और जैसे ही कहीं आग लगने की सूचना मिलती है, तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनका ड्राइवर भी इस मुहिम में सक्रिय सहयोग करता है। वन विभाग की इस तत्परता का असर साफ दिखाई दे रहा है। साल 2026 में 15 फरवरी से 7 अप्रैल तक आगजनी की घटनाओं में करीब 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जहां पिछले साल 2025 में कुल 284 घटनाएं सामने आई थीं, वहीं इस साल यह संख्या काफी घट गई है।

महुआ इकट्ठा करने के लिए लगाई जाने वाली आग जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। इससे न सिर्फ पेड़-पौधे नष्ट होते हैं, बल्कि हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर और पक्षियों जैसे वन्यजीव भी बेघर हो जाते हैं। इन हालातों से निपटने के लिए वन विभाग का मैदानी अमला दिन-रात डटा हुआ है और कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाता है। वन विभाग ने 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक नो फायर अभियान चलाया है। इसके तहत 150 चौकीदार, 70 बीट गार्ड, 25 डिप्टी रेंजर व रेंजर (महिलाएं भी शामिल), तैनात किए गए हैं। आग बुझाने के लिए 101 फायर ब्लोअर दिए गए थे, लेकिन कमी को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 19 अतिरिक्त ब्लोअर खरीदे। साथ ही जूते और टॉर्च जैसी सुविधाएं देकर कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है।

वनमंडलाधिकारी ने ओडिशा के नुआपड़ा और बरगढ़ वन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त रणनीति तैयार की है। सरायपाली क्षेत्र में पहाड़ी और घने जंगल होने के कारण यहां आगजनी की घटनाएं अधिक होती हैं, जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आग लगते ही अलर्ट मिलता है। यह सूचना सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, जहां से संबंधित रेंजर को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं।

220 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण को मिली मंजूरी

एमसीबी। जिले में बहुप्रतीक्षित 220 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को अब गति मिलने जा रही है। निर्माण स्थल पर कठोर चट्टानों के कारण फाउंडेशन कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 10 अप्रैल 2026 को नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विधिवत आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निर्माण स्थल पर हार्ड रॉक की मौजूदगी के चलते ब्लास्टिंग की आवश्यकता जताई गई थी। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ एवं नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्राप्त की। स्थल निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की जांच एवं विस्तृत परीक्षण के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अनुमोदन के आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6(क) तथा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112, 113 एवं 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमित अवधि के लिए ब्लास्टिंग की अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार ब्लास्टिंग कार्य केवल लाइसेंसधारी विशेषज्ञ की प्रत्यक्ष निगरानी में ही किया जाएगा। उपयोग में लाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ अधिकृत विक्रेताओं से ही क्रय किए जाएंगे तथा उनका भंडारण एवं परिवहन पूर्णत: नियमानुसार किया जाएगा।

महिला सभापति ई रिक्शा से पहुंच रहीं दफ्तर

■ **धमतरी नगर निगम की महिला सभापति ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक के बाद से ही उनसे गाड़ी ले ली गई.**

धमतरी। नगर निगम में इन दिनों वाहन का मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. महिला सभापति के ई-रिक्शा से निगम कार्यालय आने का मामला अब सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा विवाद बन गया है। विपक्ष ने इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं महापौर ने वाहन खराबी और आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अलग ही सफाई दी है।

नगर निगम की सभापति कौशिल्या देवांगन ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक के दूसरे ही दिन निगम प्रशासन की ओर से उनसे शासकीय वाहन वापस मांगा गया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने फोन कर वाहन ले जाने की जानकारी दी और जब बाद में वाहन के बारे में पूछा गया तो उसे खराब बताया गया।

सभापति के अनुसार, तब से लगातार वाहन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण पिछले एक सप्ताह से उन्हें किराए के ई-रिक्शा से ही दफ्तर आना-जाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन की स्थिति पहले अच्छी थी। महापौर रामू रोहरा ने मामले पर अलग पक्ष रखते हुए कहा कि सभापति, महापौर और कमिश्नर तीनों की गाड़ियां वर्तमान में खराब हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम में पहले लगभग 400 लीटर डीजल की खपत होती थी, जिसे घटाकर 200 लीटर तक लाया गया है। महापौर ने कहा कि पेट्रोल पंपों द्वारा नकद भुगतान की व्यवस्था शुरू होने से निगम को दिक्कतें आ रही हैं और आर्थिक दृष्टि से खर्च नियंत्रित करना जरूरी हो गया है।

कई वाहनों में लगातार एक से डेढ़ लाख रुपये तक मरम्मत खर्च आ रहा था, इसलिए खराब वाहनों को राइट-अफ करने और निकाय मद से नई गाड़ियों की मांग करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल किराए की गाड़ी की व्यवस्था या वैकल्पिक वाहन देना संभव नहीं है। पेट्रोल-डीजल खर्च बढ़ने के कारण करीब चार गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी हैं।

वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने निगम प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि सभापति (स्पीकर) को शहर भ्रमण और शासकीय कार्यों के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति के पास 5-6 साल पुरानी बोलेरो थी, जिसे अचानक वापस ले लिया गया और अब उन्हें ऑटो-रिक्शा से आना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महिला पदाधिकारी को हतोत्साहित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो जोरदार विरोध किया जाएगा।अब यह मामला नगर निगम की राजनीति में नया विवाद बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और सियासत तेज होने के आसार है।

सफेद हाथी साबित होता शक्कर कारखाना पेराई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

बालोद। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीतियों पर चर्चा हो रही है। उद्योग लगातार विकास कर रहे हैं लेकिन बालोद जिले में उद्योगों का जब जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बालोद जिले में एक मात्र मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया। लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही ये कारखाना सिर्फ सफेद हाथी बना हुआ है। इस कारखाने की पेराई क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन है।बावजूद इसके इस आंकड़े को कारखाना छू तक नहीं सका है। मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाने के महाप्रबंधक लिलेश्वर देवांगन ने बताया कि इस सत्र में 64 हजार मीट्रिक टन पेराई का लक्ष्य था । लेकिन 36 हजार मीट्रिक टन गन्ने की पेराई ही हो सकी। इसका मतलब ये है कि जितना लक्ष्य था उसके आधे से भी ज्यादा मात्रा की गन्ना पेराई ही संभव हो सकी।जब इस बारे में महाप्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने इसका कारण गुड़ की कीमतों में इजाफा होना बताया।इसकी वजह से दूसरे जिलों से जो गन्ना बालोद आना था वो नहीं आ सका। गन्ना उत्पादन को लेकर तो अब तक असफलता ही हाथ लगी है लेकिन अब किसानों को रिझाने प्रबंधन नया जुगाड़ लगा रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी कारखाना के कुशल संचालन के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए लेकिन परिणाम शून्य ही निकला है। अब किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए खेत तैयारी के लिए 2 हजार प्रति एकड़ देने की घोषणा की गई है। वहीं बीज में 90 प्रतिशत अनुदान जिसमें 5 रुपए का पौधा एक रुपए में दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जगदलपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ा

जगदलपुर। जगदलपुर के धरमपुरा में उस समय हड़कंप मच गया। जब एक युवक अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोगों ने युवक को देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई। मामले की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि भोपाल निवासी दीपक विश्वकर्मा का सुबह अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दीपक गुस्से के चलते धरमपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास स्थित मोबाईल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, इस घटना के तत्काल बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पड़ोसियों ने इस मामले की जानकारी युवक की पत्नी को भी दी। घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। काफी कोशिशों के बाद भी युवक नीचे नहीं आया। जिसके बादर पुलिस को बुलाया गया। युवक नीचे उतरने का नाम नही ले रहा था, वही इस दौरान युवक फोन में लगातार किसी से बात कर रहा था, करीब चार घंटे से युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस लगी हुई है।

वन विभाग का बड़ा एक्शन, गाड़ी भरकर साल के लट्ठ जब्त

एमसीबी। वनपरिक्षेत्र कुंवारपुर के बीट भुमका अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1211 में वन विभाग की टीम रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान करहीधार नाला के पास एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में साल प्रजाति के कीमती लट्ठ लोड पाए गए। जिन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि तस्कर इस कीमती लकड़ी को उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश भेजने की फिराक में थे, इससे पहले ही वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पूरे माल सहित वाहन को जब्त कर लिया। यह पूरी कार्रवाई सहायक उपवन संरक्षक (प्रशिक्षु) एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास निकुंज के नेतृत्व में की गई। टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप (पी 70 केटी 7324) को कब्जे में लिया। मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब्त लकड़ी और वाहन को वन विभाग के कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

रात में रिटायर्ड एएसआई के घर पर फिर से हो गई चोरी

कोरबा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएसईबी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड एएसआई गलेटबिन कुमार के घर पर दूसरी बार चोरी की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उसके कुछ दिनों बाद ही जनवरी माह में उनके घर पर चोरी की घटना सामने आई थी। तब 10 लाख की चोरी की घटना सामने आई थी। सोने-चांदी के जेवरात समेत नगदी चोरी हुई थी। कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक चोर नहीं पकड़े गए हैं। वहीं, चोरी की घटना फिर से सामने आई। मकान मालिक गलेटबिन ने पुलिस को फोन करके बताया कि बेटे की शादी बालको स्थित साईं मंगलम भवन में हो रही थी और वह मंगलवार की रात बारात लेकर निकले हुए थे। उन्हें सुबह पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि उसके घर पर चोरी हुई है। घर पर नगदी 20 हजार नगदी, लैपटॉप, कम्प्यूटर, टीवी और अन्य सामान रखा हुआ है। वहीं शादी कार्यक्रम में जो मेहमान आए हैं उनका समान भी है। अब क्या-क्या चोरी क्या हुई है यह आने के बाद ही पता चल सकेगा।

भिलाई केप्रतीक गंधर्व का अंडर-16 एलीट कैंप में चयन

भिलाई। भिलाई के होनहार खिलाड़ी प्रतीक गंधर्व का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित अंडर-16 मेंस एलीट कैंप के लिए हो गया है। यह चयन ऑल इंडिया जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने किया है, जिसमें देशभर के चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिलता है। प्रतीक के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के के दो अन्य खिलाड़ी अरहम नाहर और अर्शवीर सिंह भाटिया का भी चयन हुआ है, जिससे प्रदेश में खुशी की लहर है। यह एलीट कैंप 11 मई से 6 जून 2026 तक देश के अलग-अलग सेंटर में आयोजित होगा। प्रतीक गंधर्व को देहरादून सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। चयनित खिलाड़ियों को बीसीसीआई के टॉप कोचिंग स्टाफ की निगरानी में तैयार किया जाएगा। इस कैंप में खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिटनेस और इंजरी मैनेजमेंट पर भी विशेष फोकस रहेगा। एनसीए का यह कैंप युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है।

एबीवीपी द्वारा नक्सलवाद खात्मे की निकाली शव यात्रा

सूरजपुर। नक्सलवाद के खिलाफ एबीवीपी ने अनोखी शव यात्रा निकाली। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रतीक के तौर पर शव यात्रा निकाली। इस शव यात्रा का उद्देश्य देश में नक्सलवाद के अंत को दर्शाना और लोगों के बीच शांति एवं सुरक्षा का संदेश फैलाना था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद मुक्त की घोषणा की थी। तय घोषणा के मुताबिक देश में सशस्त्र नक्सलियों का अंत हो चुका है। सरकार की इस उपलब्धि को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भैयाथान क्षेत्र में एकत्रित होकर नक्सलवाद के प्रतीक स्वरूप शव-यात्रा निकाली। इसे समाप्त हुए एक युग के रूप में प्रस्तुत किया। शव-यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई और देश में शांति, विकास और सुरक्षा के नए दौर की शुरुआत का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।

अब नहीं पनपेंगे माओवादी, जरा याद इन्हें भी कर लो

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

देश से सशस्त्र माओवादी आतंक का खात्मा हो गया है। लेकिन अर्बन नक्सलियों का माड्यूल अभी भी सक्रिय है। नक्सलवाद-माओवाद के खूनी पंजों ने चारो ओर कैसे दहशत फैला रखी थी? उसकी गवाह हर वो तारीखे़ हैं जब-जब हमारे वीर जवानों ने माओवादियों से लोहा लिया। छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में, बस्तर में सुख-शांति के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसी ही इतिहास की एक तारीख़ है 6 अप्रैल 2010। ये तारीख़ याद कर लीजिए। ये वो तारीख़ थी जब दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की 62 वीं बटालियन पर घात लगाकर माओवादी आतंकियों ने हमला किया था। सुकमा (तत्कालीन दंतेवाड़ा) के चिंतागुफा, ताड़मेटला के पास माओवादियों ने क्रूरता की अति कर दी थी। लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं था। माओवादियों के साथ हुए संघर्ष में 76 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। सीआरपीएफ ने वीर बलिदानियों को याद करते हुए लिखा —हमारे 75 श्रेष्ठ जवानों ने 6 घंटे तक चले भीषण संघर्ष में 7 माओवादियों को ढेर किया और 8 को घायल किया, इसके बाद उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 500 से अधिक भारी हथियारों से लैस माओवादियों और सैकड़ों

आईईडी से घिरे होने के बावजूद—जो लगभग हर उस स्थान पर लगाए गए थे। जहाँ हमारे जवान शरण लेकर जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। उनका साहस अद्वितीय और अविस्मरणीय था।हमारे कुछ वीरों ने अपने साथियों की रक्षा करने और दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए ग्रेनेड पर लेटकर सर्वोच्च बलिदान दिया। अंतिम क्षणों में भी वीर सैनिकों ने अपने हथियार अपने नीचे छिपा लिए। इस क्रूर हमले का मास्टरमाइंड माडवी हिड़मा था। इसके बाद जेएनयू में अर्बन नक्सलियों ने जश्न मनाया था। दंतेवाड़ा क्षेत्र में हमले के समय डीआईजी रहे आईपीएस कल्लूरी ने जेनएयू में हमले के बाद हुए जश्न की चर्चा करते हुए कहा था —मुझे काफी दु:ख पहुँचा था जब मुझे यह पता चला कि जेनएयू में (कुछ विद्यार्थियों द्वारा) ताड़मेटला में 76 बलिदानी जवानों के बलिदान का जश्न मनाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के कांकेर समेत कई अलग-अलग इलाकों में अर्बन नक्सलियों ने जवानों के बलिदान पर जश्न मनाया। इस घटना को अर्बन नक्सली कही जाने वाली अरुंधति राय की पुस्तक, रिपोर्टिंग के लिए भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि इस घटना वाले दिन से अगले— 19 दिन तक अरुंधति राय दंतेवाड़ा में रुकीं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, जो सेना, प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में थी। अब आप सोचिए कि जहां एक ओर हमारे 76 जवानों का बलिदान हो गया। वहीं दूसरी ओर अर्बन नक्सली। इसे जीत के तौर पर देख रहे थे। भारत के ख़िलाफ़ छेड़े गए सशस्त्र युद्ध के इस घटनाक्रम पर जश्न मना रहे थे। सेना, पुलिस और सरकार के ख़िलाफ़ प्रोपेगैंडा वाली रिपोर्टिंग की जा रही थी। उन्हें खलनायक बताया जा रहा था। जबकि माओवादी आतंकियों की रहनुमाई की जा रही थी। क्योंकि अर्बन नक्सलियों के लिए माओवादियों के द्वारा जवानों की हत्या—जीत थी। इसे वो बड़े माड्यूल के तौर पर फैलाना चाहते थे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अर्बन नक्सलियों और सशस्त्र माओवादियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये दोनों न तो देश के संविधान को मानते हैं। न ही इनमें राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा है। इनका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि- कैसे भारत में रक्तपात किया जाए। जल-जंगल, जमीन के नाम पर हिंसा की जाए। ये दोनों जनजातीय समाज के, वनवासियों के घोर शत्रु हैं।अर्बन नक्सलियों और सशस्त्र माओवादियों के रक्तपात के चलते ही— सुदूर वनांचल क्षेत्र विकास से बहुत पीछे रह गए। हालांकि जैसा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि— यह अर्बन नक्सल खुद हाथ में हथियार नहीं लेना चाहते, लेकिन गरीबों के हाथ में हथियार देकर अपनी विचारधारा फैलाना चाहते हैं। मगर उनके भी दिन लद गए हैं।ये कथन इस बात की प्रतिपुष्टि करता है कि हथियारबंद माओवादियों के बाद अगला नंबर अर्बन नक्सलियों का है। जो भी भारत की अखंडता, संप्रभुता और संविधान के ख़िलाफ़ आएगा। वो बख़्शा नहीं जाएगा। मातृभूमि भारतभूमि को हम रक्तरंजित नहीं होने दे सकते। हमारे वीर जवानों ने सुरक्षा के लिए जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है। वर्षों तक माओवादियों की मांद में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद किया है।आज उन वीर बलिदानियों के कारण ही छत्तीसगढ़ खूनी आतंक से बाहर आया है। सशस्त्र माओवादी आतंक का सफाया हो चुका है।

संक्षिप्त समाचार

नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार दुर्गावती कुंजाम सस्पेंड, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ निर्सिंग कउंसिल की रजिस्ट्रर दुर्गा उसारे को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता देने, वित्तीय अनियमितताएं, पद का दुरुपयोग समेत अन्य लापरवाही पाए जाने पर की गई है। उन्हें प्रभार से हटाते हुए रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से निलंबन आदेश जारी हुआ है। विभागीय जांच में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रस्तावित करना, वित्तीय अनियमितता करना, शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना, तथ्यों को छुपाकर भ्रमित जानकारी प्रस्तुत करना, नियम विरूद्ध कार्य करना और स्वहित में पद का दुरूपयोग करना पाया गया। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दुर्गा उसारे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत लागू होता है। वहीं उन्हें रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में अटैच किया गया है।

पावर कंपनी के डायरेक्टर पाठक को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज

मुख्यालय के सेवाभवन में आयोजित समारोह में डायरेक्टर (वाणिज्यिक एवं नियामक मामले) श्री आर.ए.पाठक को में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर ऊर्चा सचिव एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। डॉ. यादव ने उनके कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पावर कंपनी के निदेशकगण सर्वश्री एस.के.कटियार, आर.के.शुक्ला एवं भीमसिंह कंवर विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री पाठक ने अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सहित पावर कंपनीज में 41 वर्षों तक सेवाएं दीं। उन्हें अप्रैल 2025 में निदेशक पद पर राज्य शासन ने नियुक्त किया था, जुलाई में वे कार्यपालक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका कार्यकाल पूरा होने पर पावर कंपनी में आयोजित विदाई समारोह में अध्यक्ष डॉ. यादव ने उनके व्दारा 41 वर्षों की सेवाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी कार्यक्षमता और कार्यशैली अलग थी। उन्होंने अपना कार्यकाल समर्पण एवं निर्भिकता से पूरा किया।

अभा स्वास्थ्य विज्ञान कुलपति सम्मेलन 10 को आयुष विश्वविद्यालय में

रायपुर। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति

स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा शुक्रवार को अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित समस्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों का सम्मेलन का मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा के मानकों, मूल्यांकन में पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए; तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के भारतीयकरण पर शोध करने और उसे बढ़ावा देने के लिए है। इसी विषय पर विभिन्न सत्रों में देश के विशेषज्ञ कुलपति एवं वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षाविद चर्चा करेंगें। सम्मेलन में चर्चा उपरांत शासन के नीति निर्धारकों को अनुशंसा प्रेषित की जायेगी। इस अवसर पर पहले सत्र केमुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह होंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रुप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कराड कुलाधिपति के मुख्य सलाहकार डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष डॉ. राजीव सूद तथा आयुष विवि के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा उपस्थित रहेंगे।

खटवा बरदर डायवर्सन योजना के कार्यों के लिए 19.02 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर की खटवा बरदर डायवर्सन योजना के लिए 19 करोड़ 02 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के निर्माण से 400 हेक्टेयर खरीफ एवं 80 हेक्टेयर रबी सहित कुल 480 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकपुर को डायवर्सन योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली दौरे पर सीएम साय, बस्तर बनेगा सबसे समृद्ध संभाग : केदार

■ मंत्री ने कहा- छत्तीसगढ़ के विकास में पड़ेगा बड़ा असर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर का ब्लू प्रिंट सौंपा है। आने वाले समय में बस्तर और छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा असर पड़ेगा।सरकार की मंशा है कि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था और अधोसंरचना का निर्माण हो। मुख्यमंत्री के प्रयास के कारण ही प्रधानमंत्री की जो मंशा है वह पूरी हुई है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम करेगी।

लगातार भूजल स्तर में गिरावट को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा, लगातार भूजल का दोहन करेंगे तो जलस्तर में गिरावट आएगी। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। गर्मी की फसल में कम से कम भूजल का दोहन हो, कई जगह पर इस पर पाबंदी लगाई है। किसानों ने भी इस पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है।

कांग्रेस की होने वाली बैठक को लेकर केदार कश्यप ने कहा, पिछले सवा दो वर्षों से कोशिश से जारी है। मेरी शुभकामनाएं है कि जो अंदरूनी झगड़े हैं उससे निजात पाए, फिर बाद में सड़क पर आए। यह अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है, उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आजादी के लंबे समय बाद भी इस देश, राज्य और क्षेत्र में शासन किया और उनके लिए क्या योजना बनाई, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन की दृष्टि से हमारी सरकार ने काम किया। पिछली सरकार ने उन योजनाओं को बंद करने का काम किया तो उनका भी जवाब उन्हें देना चाहिए।

नक्सलमुक्त गांव को एक करोड़ रुपए देने को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, पंचायत के तहत घोषणा की गई थी। बहुत सारी पंचायत को इसमें लिस्टिंग किया गया है। जो खुद से आकर नक्सल मुक्त पंचायत के रूप में अपने आप को घोषित करें उसके लिए प्रावधान था। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार लगातार उस क्षेत्र को सपोर्ट कर रही है। आने वाले समय में सबसे समृद्ध संभाग के रूप में हमारा बस्तर संभाग होगा।

खड़गे को 'पागल' कहने पर भड़के कांग्रेसी असम सीएम हिमंत का जलाया पुतला

■ कहा- दलित नेता का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त

रायपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। यह विरोध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर किया गया।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि सभ्य समाज इस तरह की भाषा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में उन पर इस प्रकार के आरोप लगाना निंदनीय है। मेमन ने कहा कि इस तरह के बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि घबराहट में दलित नेता का अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया है। यदि इस तरह के बयान पर रोक नहीं लगी तो आगे और भी उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

बता दें कि टीओक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को सच की रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है और वे 'पगला' गए हैं। उनके जैसे वरिष्ठ नेता को बिना तथ्यों के ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान उस समय आया, जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनके परिवार की नागरिकता और पासपोर्ट मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

कांग्रेस कार्यकारिणी गठित नहीं होने पर पीसीसी नाराज

जिला अध्यक्षों की बैठक : 15 अप्रैल तक पूरा करने का अल्टीमेटम

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के अध्यक्ष, पीआर प्रभारी मैजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों से बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जानकारी मांगी गई। इस दौरान कार्यकारिणी गठन की धीमी प्रक्रिया पर पीसीसी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला कार्यकारिणी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटियों का गठन तय समय सीमा तक कर लिया जाए। कार्यकारिणी गठन की धीमी प्रक्रिया के चलते संगठन के अन्य टास्क समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे एल, ताम्रध्वज साहू, शिवकुमार डहरिया सहित संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बताया जा रहा है कि जिला कार्यकारिणी के गठन में एआईसीसी के निर्देशानुसार केवल 31 ही सदस्यों की अनुमति मिली है, जिसके चलते ही कार्यकारिणी गठन में लेट लतीफी सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बड़े विधानसभा वाले जिलो में सिर्फ 31 सदस्यों की कार्यकारिणी गठन करना मुश्किल है। इससे संगठन के नेताओं में नाराजगी बढ़ेगी इसलिए लगभग आधा दर्जन जिलों में कार्यकारिणी गठन को रोक कर रखा गया है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कई जिलों में कार्यकारिणी गठन का पेंच स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के खींचतान की वजह से भी फंसी हुई है, क्योंकि एआईसीसी ने जिला कार्यकारिणी गठन की संख्या 51 से घटाकर 31 सदस्यों तक समिति कर दी है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में पीसीसी ने जिला अध्यक्षों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 15 अप्रैल तक जिला कार्यकारिणी और बूथ कमेटी का गठन करने का अंतिम समय दिया है। गौरतलब है कि राज्य की राजधानी रायपुर के शहर और ग्रामीण, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलौदाबाजार समेत कई जिलों में कार्यकारिणी का गठन अब तक अटका हुआ है।

बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रभारियों की अहम बैठक आज हुई है। एआईसीसी के निर्देश और पीसीसी के मार्गदर्शन में सभी जिला अध्यक्षों को जो जिम्मेदारियां और टारगेट दिए गए थे, उनकी समीक्षा की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा भी की गई। बूथ गठन को लेकर विशेष चर्चा हुई है, वहीं विलेज कमेटियों का गठन तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन बाकी है, जिस पर जल्द काम पूरा किया जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों को 15 अप्रैल को संगठन को लेकर नया टास्क दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कई जिलों में बनेंगी फोरलेन सड़कें, लोक निर्माण विभाग द्वारा 708 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

विभाग ने रायगढ़ में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 49 लाख रुपए, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 55 करोड़ 29 लाख रुपए, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 81 करोड़ 48 लाख रुपए तथा 6 किमी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपए, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी लंबाई के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपए, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार रुपए एवं कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई के तीन सड़कों के फोरलेन में उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री आज करेंगे पंडित रविशंकर त्रिपाठी एवं शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाओं का अनावरण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 09 अप्रैल 2026 को सरगुजा जिला प्रवास के दौरान पंडित रविशंकर त्रिपाठी एवं शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।अनावरण कार्यक्रम अम्बिकापुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास पंडित रविशंकर त्रिपाठी चौक में दोपहर 02:30 बजे आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री श्री अरुण साव करेंगे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि आदिम जाति विकास कृषि विकास कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मछलीपालन पशुधन विकास विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त वाणिज्यिक कर आवास एवं पर्यावरण योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री सरगुजा श्री ओपी चौधरी, पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री नारायण चन्देल, गृह निर्माण मण्डल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, राज्य युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर नगर पालिक निगम अम्बिकापुर श्रीमती मंजूषा भगत, सभापति नगर पालिक निगम अम्बिकापुर श्री हरमिन्दर सिंह टिन्नी, प्रभारी सदस्य महापौर परिषद एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 15 श्री मनीष सिंह एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 16 श्री गीता प्रजापति होंगी।

विश्व नवकार दिवस पर सकल जैन समाज का तीन दिवसीय धार्मिक शिक्षण शिविर आज से

रायपुर। शासनप्रभाविका प्रवर्तिनी प पु श्री निपुणा श्री जी म सा की सुशिष्या प्रवचन प्रवीणा श्री स्नेहयशा श्री जी म सा आदि ठाणा - 9 अप्रैल प्रात: 6.30 बजे भैरव सोसायटी पधार रहे हैं। श्री सुधर्म विहार के सामने एकत्र होकर सकल जैन समाज व भैरव सोसायटी जैन श्रीसंघ गुरूवर्या की अगवानी करेंगे। श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद व महासचिव महेन्द्र कोचर ने बताया कि गुरूवर्या की निश्रा में प्रात: 8.30 बजे से नवकार जाप होगा।

प्रात: 9 बजे से 11 बजे तक महिलाओं का धार्मिक शिक्षण शिविर आराधना केंद्र में होगा। शिविर में संस्कारों का शंखनाद, स्वंय को जानो - पहचानो- और पहुँचो विषय पर साध्वी जी का प्रवचन होगा। दोपहर को 3 से 5 बजे तक छठवीं से बड़े बच्चों का धार्मिक अध्ययन साध्वी जी की निश्रा में होगी। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री सीमंधर स्वामी का जन्मकल्याणक महोत्सव वैसाख वदी दसमी 12 अप्रैल रविवार को जैन साध्वी श्री स्नेहयशा श्री जी की निश्रा में मनाया जाएगा। विधिकारक श्री विमल गोलछा द्वारा सत्तरभेदी महापूजन का विधान होगा। तीर्थंकर की माता रानी द्वारा देखे गए 14 महास्वप्नों का चढ़ावा बोला जाएगा। भगवान श्री सीमंधर स्वामी जी के पालना जी की आराधना की जावेगी।

ट्रस्टी नीलेश गोलछा व टीकम जैन ने बताया कि सत्तरभेदी पूजन के साथ ही जिनमंदिर व चमत्कारी दादाबाड़ी के शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई जावेगी। श्री सीमंधर स्वामी मूलनायक की अमर ध्वजा के लाभार्थी मूलचंद संतोष सरला देवी बैद परिवार, चमत्कारी श्री जिनकुशल सूरि जैन दादाबाड़ी की अमर ध्वजा लाभार्थी श्री जिनकुशल सूरि जी की ध्वजा श्री तिलोकचंद, शांतिलाल, अशोक कुमार बरडिया परिवार , श्री जिनदत्त सूरि जी की ध्वजा श्रीमती पुष्पादेवी कोठारी मनोज कविता कोठारी परिवार, श्री मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरी जी की ध्वजा महेन्द्र कुमार मीना, तरुण कुमार मोना, मानस, गौरव प्रेरणा , दिया कल्प गर्वित प्रेरित कोचर द्वारा फहराई जावेगी। 12 अप्रैल 2026 रविवार रात्रि 8 बजे से दादागुरुदेव इक्तिसा जाप व श्री सीमंधर स्वामी जन्मकल्याणक प्रभुभक्ति होगी।

आई-गॉट में सभी विभागों को ऑन-बोर्ड होना जरूरी : मुख्य सचिव

■ आई-गॉट साधना सप्ताह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मिशन कर्मयोगी कार्यशाला हुई आयोजित

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से कहा है कि वे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई-गॉट ट्रेनिंग कार्यक्रम से अपने विभाग को अनिवार्य रूप से ऑन-बोर्ड कर लें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ऑन-बोर्ड हो जाये मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अपने मोबाईल से ऑन-बोर्ड होने को कहा है। राज्य शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभागीय स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग की आवश्यकता अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स तय कर लें, जिससे उन्हे प्रशिक्षित किया जा सके। आज आई-गॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत साधना सप्ताह के मौके पर सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी को कर्मयोगी मिशन के तहत प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य शासन के विभागों के प्रमुख अधिकारी सहित विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।

कार्यशाला के प्रारंभ में बताया गया की कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई-गॉट और ई-एच.आर.एम.एस. से जुड़ते हुए उनकी क्षमता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि 'आई-गॉट' प्लेटफॉर्म पर ए.आई का उपयोग बढ़ रहा है और यह कर्मचारियों को स्मार्ट एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने शत् प्रतिशत ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया। कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण केवल कौशल विकास तक ही नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने विभाग की योजनाओं और कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

दावा-आपत्ति

1. बच्चे का नाम	-	माया
2. बच्चे का प्राप्ति दिनांक	-	15/11/2025
3. संस्था	-	सेवा भारती मातृछाया दुर्ग
4. पता	-	बम्बलेश्वरी कालोनी, नरनारायण मंदिर के पास, धनोरा रोड़ बोरसी, दुर्ग (छ.ग.)
5. रंग	-	गोरा
6. उम्र	-	04 माह

उक्त बालिका दिनांक 15/12/2025 को बाल कल्याण समिति, दुर्ग के आदेश क्रमांक 798/बाकस/25-26 दुर्ग, दिनांक 15/12/2025 से अस्थाई संरक्षण हेतु सेवा भारती मातृछाया दुर्ग (छ.ग.) में रखने हेतु आदेशित किया गया है।

सर्व संबंधित को जो कि बालिका के वैधानिक पालक / अभिभावक होने का दावा आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दुर्ग अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण सेवाभारती दुर्ग (छ.ग.) मे दर्ज करा सकते हैं। उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जायेगी। यह विज्ञापन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

जी-262700076/3 **दूरभाष क्र-0788-2213363, 9907407044**

चूहे को शेर बताकर किसको डराना चाहती हैं ममता?

नीरज कुमार दुबे

भारत के खिलाफ जहर उगलने के आदी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जब कोलकाता को निशाना बनाने की धमकी दी तो यह उनकी बौखलाहट का खुला प्रदर्शन था, लेकिन हैरानी इससे भी ज्यादा इस बात पर है कि भारत के भीतर कुछ नेता इस खोखली धमकी को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जिसे बार-बार उसकी हर हरकत पर मुंहतोड़ जवाब मिला हो, जिसे उसकी गुस्ताखियों की सजा उसके घर में घुसकर दी गई हो, उसकी गीदड़ भभकी पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का शोर मचाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि चिंताजनक भी है। देखा जाये तो यह एक कमजोर और बेअसर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और चूहे को शेर बताकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने पिछले सप्ताह सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया था कि भविष्य में भारत के साथ होने वाला कोई भी संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और पाकिस्तान कोलकाता जैसे बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। देखा जाये तो पाकिस्तान की इस ताजा धमकी को भारत में गंभीरता से कम और हास्य के रूप में अधिक लिया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सैन्य क्षमता, तकनीक और खुफिया तंत्र पाकिस्तान से कहीं अधिक मजबूत है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी केवल मानसिक दबाव बनाने का असफल प्रयास है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू देश के भीतर की राजनीति बन गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी सरकार आने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने इस धमकी पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? दूसरी ओर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहसिक हरकत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके बारे में इतना कहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम होगा ये भविष्य में पता चल जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने खास तौर पर कोलकाता का नाम क्यों लिया? देखा जाये तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण छिपे हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि वह केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने का दावा करता है। कोलकाता जैसे ऐतिहासिक और प्रमुख शहर का नाम लेकर वह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान जानता है चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में वहां की राजधानी का नाम लेना तुरंत ही सुर्खियों में ला सकता है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले से ही सीमा और घुसपैठ के मुद्दे गर्म रहते हैं। ऐसे में कोलकाता का नाम लेकर पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आंतरिक राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करना चाह रहा है।

बागी सिपाहियों को सबक सिखाने के मूड में कांग्रेस

उमेश चतुर्वेदी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का दांव चूंकि दो राज्यों में ही सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका सारा ध्यान इन्हीं दो राज्यों पर है। असम और केरल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति अलग-अलग है। इसलिए दोनों ही राज्यों में उसकी चुनौतियां अलग हैं, इसलिए उसकी लड़ाई के रूप और तरीके अलग-अलग हैं। हरियाली और समुद्री किनारे के चलते केरल को खूबसूरत राज्यों में शुमार किया जाता है। इस खूबसूरती की ही वजह से केरल को 'भगवान का देश' कहा जाता है। बारह साल से केंद्रीय सत्ता से दूर कांग्रेस को उम्मीद भगवान के इसी देश से ही ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह इस राज्य से उसे समर्थन मिला था, उसकी वजह से उसकी उम्मीदों का परवान चढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यहां उसकी चुनौती भगवान को न मानने वाली विचारधारा से है। केरल की सत्ता पर काबिज जिस वाममोर्चा से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ बने विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस उसी वाममोर्चे के साथ है।

स्थानीय स्तर पर विरोध और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का विरोधाभास अगर सर्वाधिक शिक्षित राज्य में भारी पड़ सकता है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में राजधानी तिरूअनंतपुरम् में जीत हासिल कर चुकी बीजेपी इस विरोधाभास को खूब उछाल रही है। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि इस बार भगवान के देश में भगवा ध्वज फहरने जा रहा है, हालांकि अब तक चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी को वैसी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी का मौजूदा जीन आखिरी दम तक हार नहीं मानने का है। इसलिए पार्टी की कोशिश सीपीएम की अगुआई वाले वाममोर्चे और कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त मोर्चे के विरोधाभास को उजागर करने पर है।

पार्टी को लगता है कि देश के इस सर्वाधिक साक्षर राज्य में अगर जनता ने इस विरोधाभास को समझ लिया तो राज्य के चुनावी नतीजे 2017 के उत्तर प्रदेश के परिणामों की तरह आश्चर्यजनक रूप से अपने पक्ष में किए जा सकते है। 2017

में किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। इसी कोशिश के तहत अमित शाह केरल की करीब 19 प्रतिशत जनसंख्या वाले ईसाई समुदाय से लगातार संपर्क कर रहे हैं।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल के कुल 3.34 करोड़ निवासियों में से लगभग 61.41 लाख ईसाई हैं, जो मुख्य रूप से मध्य केरल में केंद्रित हैं। पारंपरिक रूप से केरल में यह समुदाय कांग्रेस का सहयोग करता रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश इस समुदाय को कांग्रेस से तोड़ने की रही है। हालिया अतीत के कुछ चुनावों में यह समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आया है। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लव जेहाद का शिकार केरल में यह समुदाय भी होता रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर इस समुदाय में भी कुछ वैसा ही गुस्सा है, जैसा उत्तर भारत में हिंदू समाज में ऐसा नजर आता है। कांग्रेस का संकट है कि वह वाममोर्चा का विरोध और समर्थन की उलटबांसी की सटीक काट नहीं खोज पा रही है। इस वजह से राज्य का चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे बीजेपी जिस तरह की कोशिश करती नजर आ रही है, उससे सबसे ज्यादा संकट में कांग्रेस की संभावनाएँ ही नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को इस राज्य की सत्ता से दूर रखने की ही है।

पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य असम की जहां तक बात है, तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। कांग्रेस की चिढ़ यह है कि बीजेपी जिस हिमंत विस्वसरमा के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, वह कभी कांग्रेस का ही चेहरा होते थे। कांग्रेस अपने इस पूर्व नेता को इस बार हर हाल में सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन-तीन पासपोर्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का आरोप है कि रिन्की भुइयां सरमा के पास संयुक्त अरब अमीरता, एंटीगुआ और बारबुडा एवं मिस्र का पासपोर्ट है। कांग्रेस ने इसके समर्थन के कुछ दस्तावेज़ों की कॉपी भी दिखाई है।

हालांकि हिमंत विस्व सरमा का कहना है कि कांग्रेस हताशा में है और उनकी ओर से कांग्रेस के नेताओं पर मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस एक तरह से अपने इस पुराने सिपाही को भ्रष्टतम साबित करने की कोशिश में है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि हिमंत के पास अमेरिका में भी कंपनी है, जिसमें बावन हजार करोड़ रूपए जमा हैं। कांग्रेस का यह आरोप राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार ही लगता है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पुराने सहयोगी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। राहुल गांधी उन्हें सत्ता में वापसी के बाद जेल भेजने की बात कहते रहे हैं। कांग्रेस की इन आरोपों के जरिए कोशिश सिर्फ हिमंत को ही सवालों के घेरे में रखना नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी भ्रष्टाचार बताने की भी है। वैसे हिमंत भी राहुल गांधी की आलोचना करते रहे हैं। अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह वे राहुल गांधी को ही बताते रहे हैं। दोनों के रिश्तों के संदर्भ में मौजूदा आरोपों को देखें तो यह निजी खुन्नस का भी मामला लगता है। हिमंत इन आरोपों को निजी खुन्नस बताने और असम के लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हैं। अगर वे इसमें कामयाब रहे तो असम में कांग्रेस की चुनावी संभावना दूर होगी।

अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए उत्तर पूर्व में अपनी मौजूदगी बनाए रखना दूर की कौड़ी हो जाएगा। इसका कारण यह है कि हिमंत पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी का चेहरा और संकट मोचक बन चुके हैं। अगर कांग्रेस की कोशिशें कामयाब रहीं तो पूर्वोत्तर में बीजेपी की राह कठिन हो जाएगी। हिमंत की हार उसकी चुनावी संभावनाओं पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर उभरेगी। असम पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ने अपने हरावल दस्ते के हर हथियार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की कोशिशों को पलीता उसकी प्रेस कांफ्रेंस में ही लगता दिखा, जब राष्ट्रीय मीडिया के एक पत्रकार ने उस कंपनी की वेबसाइट खोलकर उसकी स्थापना के तथ्य कांग्रेस प्रवक्ता के सामने पेश करने शुरू कर दिए, जो कांग्रेस के दावे के ठीक उलट नजर आ रहे थे। इसका माकूल और संतोषजनक जवाब कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाए।

असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां तो वह लड़ती भी नहीं दिख रही। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस की सिपाही रहीं। केरल की तरह पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस विरोधाभास से जूझ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वह ममता के साथ है, लेकिन राज्य में उसकी पूरी कोशिश ममता को हिमंत की तरह सबक सिखाने की ही लग रही है। दरअसल राज्य में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है।

हालांकि 2023 में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की सगरदीघी सीट के उपचुनाव में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को हराकर विधानसभा में अपना खाता खोलने में सफल रही थी। मुस्लिम बहुल विधानसभा में कांग्रेस की जीत से ममता की नींद उड़ गई थी। राज्य के करीब पैंतीस फीसद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध का डर उन्हें सताने लगा। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सगरदीघी शुरू किया और यहां से जीते कांग्रेसी विधायक बायरन विश्वास को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा दिया। कांग्रेस ने इसे विश्वासघात माना और लगता ऐसा है कि वह ममता को इन चुनावों में सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की ग्यारह मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी पहले नंबर पर रहे थे। इसलिए कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनावों में उसे मुस्लिम वोटरों का साथ मिल सकता है। उसकी पूरी रणनीति इसी लिहाज से आगे बढ़ रही है।

साफ है कि इस बार के चुनावों में कांग्रेस जहां अपने पुराने सिपाहियों को सिखाने की कोशिश में है, वहीं खुद की संभावनाएं बेहतर करने का भी प्रयास कर रही है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अर्थात्- निष्काम दृष्टि से किया हुधा थोड़ा सा भी कम्म बड़े भारी भय से बचा देता है। सो इन्द्रदेव ने भी यह सब कार्य समस्त देवताओं की ग्राज्ञा से अपना कर्तव्य समझ कर किया था। इसमें उनका निजी कुछ भी स्वार्थ न था बल्कि सब की आपत्ति अपने ऊपर उठाकर उपकार करना उनका ध्येय था। यही कारण है कि इस परोपकार का अन्तिम परिणाम भी इन्द्रदेव के लिये महा-वरदान सिद्ध हुवा जो सहस्राक्ष रूप में प्रत्यक्ष दीख पड़ता है।

विश्वरूप वध से ब्रह्महत्या

इन्द्रदेव के ऊपर दूसरा आक्षेप यह किया जाया करता है कि उन्होंने विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण को जब कि वह यज्ञ में पुरोहित का काम कर रहा था- मार डाला, अत: वे ब्रह्म-हत्यारे हुवे। इन्द्रदेव का यह कर्म अध्यन्त धर्म- विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त पुराणों में जिस विश्वरूप का इस्स तरह मारा जाना अङ्कित है, उसका रूप भी बड़ा ही विचित्र लिखा है, यथा-उसके तीन मुख थे, एक से वह सुरा (शराब) पीता था दूसरे से सोम (याज्ञिक रस) पीया करता था, एवं तीसरे से अन्न खाया करता था। इस तरह यह आख्यान धर्म-विरुद्धता एवं असंभवतासे परिपूर्ण है। हम क्रमागत शैली के अनुसार सर्वप्रथम इसका वैदिक-स्वरूप प्रकट करते हैं ।

वैदिक स्वरूप

(क) त्वष्टुर्ह वै पुत्र: । त्रिशीर्षा षडक्ष आस । तस्य त्रीण्येव मुखान्यासुस्तद्यदेव। रूपरास, तस्माद् विश्वरूपो नाम। तस्य सोमपानमेवैकं मुखमास सुरापाणमेकमन्नस्याऽशनायैकं, तमिन्द्रो दिद्वेष तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद। यत्सोमपानमास तत: कपिञ्जल: समभवत्, अथ यत्सुरापाणमास, तत: कलविङ्क: समभवत्, अथ यदन्नस्याऽशना-यास ततस्तित्तरि: समभवद्। (शतपथ 1 16 13 12-5)

क्रमश: ...

विश्व णमोकार दिवस

ललित गर्ग

विश्व इतिहास के इस संक्रमणकाल में, जब मानवता युद्ध, हिंसा, आतंक, तनाव और असहिष्णुता के बोझ तले कराह रही है, ऐसे समय में 9 अप्रैल 2026 को मनाया जाने वाला विश्व णमोकार मंत्र दिवस एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा-विस्फोट के रूप में सामने आ रहा है। यह दिवस केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिव्य चेतना के जागरण का ऐसा अवसर है, जिसमें सामूहिक मंत्रोच्चारण से उत्पन्न होने वाली चमत्कारी और सिद्ध शक्तियां पूरे विश्व को आलोकित करने वाली हैं। एक विश्व, एक दिन, एक मंत्र-इस संकल्प के साथ प्रात: जब संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ णमोकार महामंत्र का उच्चारण होगा, तब यह केवल ध्वनि नहीं होगी, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा तरंग का निर्माण होगा।

आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार, जब लाखों-करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उससे उत्पन्न स्पंदन वातावरण को शुद्ध करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय करते हैं, सकारात्मक चेतना का तीव्र प्रसार करते हैं और शांति एवं अहिंसा का शंखनाद करते हैं। यह सामूहिक ऊर्जा 'संकल्प शक्ति' के रूप में कार्य करती है, जो असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है।

यह विलक्षण दिवस हजारों मंदिरों एवं अन्य स्थलों में जातीय बंधनों को तोड़कर सभी समुदाय, जाति, वर्ग के लोगों को सम्मिलित होने का अवसर देकर एक प्रेरणादीप बनेगा, जहां मैत्री के फूल खिलेंगे, शांति एवं सद्भावना की ज्योति रश्मियां जगमगायेगी। मानव ने ज्ञान-विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति की है। परन्तु अपने और औरों के जीवन के प्रति सम्मान में कमी आई है।

विचार-क्रान्तियां बहुत हुईं, किन्तु आचार-स्तर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन कम हुए। शान्ति, अहिंसा और मानवाधिकारों की बातें संसार में बहुत हो रही हैं, किन्तु सम्यक्-आचरण, सम्यक्-चरित्र, सम्यक्-दृष्टि का अभाव अखरता है। सिद्ध एवं चमत्कारी णमोकार महामंत्र सम्यक्-आचरण को उद्घाटित करने वाला किसी धर्म विशेष का नहीं है, यह एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदैशिक मंत्र है, जिसका उच्चारण कर व्यक्ति शुद्ध आचरण एवं स्वस्थ जीवनशैली को आकार देते हुए शांति, अहिंसा, अयुद्ध, सह-जीवन का साकार कर सकता है। 'णमोकार महामंत्र' के सामूहिक उच्चारण के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है।

यह आयोजन विश्व शांति, आत्मशांति, सद्भावना और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन-जीतो संस्था के द्वारा कराया जा रहा है। इस विराट आयोजन में 180 से अधिक देशों के लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। विश्वभर में 100 से अधिक मेगा इवेंट्स और 6000 से अधिक मंदिरों एवं स्थलों पर यह सामूहिक जाप होगा।

बर्बादी के कगार पर पहुंचा ईरान भी प्रतीत हो रहा विजेता

एस प्रसन्नराजन

जंग कौन जीत रहा है-अगर युद्ध के मैदान में नहीं, तो कहीं और? मौजूदा मीडिया की तस्वीर यही दिखाती है कि ट्रंप हार रहे हैं। यह करारी हार की ही तैयारी थी कि तीव्र आवेग से भरा एक राष्ट्रपति, बिना किसी रणनीति के (एक जरूरतमंद रणनीतिक साझेदार के बोझ तले दबा हुआ और 'महान अमेरिका' के सम्राट के तौर पर अपनी ही आभा से अंधा होकर) एक देश पर बमबारी करने चला गया।

इस तस्वीर (नैरेटिव) की रोचकता उस विजेता (ईरान) की मजबूत इच्छाशक्ति से और बढ़ जाती है, जो लहूलुहान होते हुए भी सांस ले रहा है।

यह एक ऐसे क्रांतिकारी गणतंत्र की कहानी दिखाता है, जो इतिहास के लंबे युद्धों की भट्ठी में तपकर और भी मजबूत हो गया है। उसमें अपनी पीड़ा को प्रतिरोध में, सैन्य असमानता को एक मौलिक आक्रमण में, अपनी भौगोलिक स्थिति को शस्त्रागार में, और अपनी आस्था के ताने-बाने को एक ऐसी अभेद्य मशीन में बदलने का अदम्य संकल्प है, जिसे कोई भी शक्ति काट या नष्ट नहीं कर सकती। एक तीसरा पक्ष (इस्राइल) भी है (ज्यादातर तस्वीरों में यही पहला पक्ष होता है), जो अपने अस्तित्व को लेकर इतनी ज्यादा और लाइलाज आशंकाओं में डूबा हुआ है कि उसने इस युद्ध को हर देश के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मुख्य सामाजिक आधार के साथ विश्वासघात करने पर मजबूर कर दिया, और उन्हें एक ऐसे दूरदराज के दलदल में घसीट लिया है, जहां राष्ट्रवादी लाभ तो बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक नुकसान कहीं ज्यादा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं, जैसे एक और वियतनाम युद्ध की स्थिति बनती दिख रही हो और यह अमेरिका के राष्ट्रपति पद को कमजोर कर रहा है, जिससे देश पहले से ज्यादा छोटा और कमजोर नजर आ रहा है।

ईरान के खिलाफ जंग असल में लोगों के जहन में ज्यादा असरदार ढंग से लड़ी जा रही है, जहां विचारधाराओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया

जा रहा है, ताकि यह साफ हो सके कि विजेता कौन है और हारने वाला कौन। इसलिए, भले ही ऊपर जमीन पर नुकसान हो रहा हो, पर ईरान के नेता अंदर से खुद को मजबूत महसूस कर सकते हैं। यहां तीन चीजें काम कर रही हैं।

पहला, अमेरिका-विरोध और ट्रंप-विरोध का मेल। अमेरिका के प्रति राजनीतिक और साथ ही सांस्कृतिक विरोध शीतयुद्ध से चला आ रहा है। नए रूप में यह अमेरिका-विरोध (या वैचारिक रूप से आहत लोगों के लिए साम्राज्यवाद-विरोध) हर बार असर डालता है, जब अमेरिका अपनी शर्तों के अनुसार आजादी की परिभाषा तय करने की कोशिश करता है। यह तथ्य कि अमेरिका का राष्ट्रीय हित तथाकथित 'अंतरराष्ट्रीय नैतिकता' से हमेशा मेल नहीं खाता और उदारवादियों के आत्म-सच्चाई के भाव को और भी दृढ़ बनाता है। अब, जब ट्रंप ने अमेरिका की छवि को अपने तरीके से बदल दिया है, जो कई लोगों को डराने वाला लगता है, खासकर उन्हें, जो सच, कानून और विनम्रता जैसे पुराने मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो साम्राज्यवाद-विरोध को एक उपयुक्त और राक्षसी चेहरा मिल गया है। पश्चिम-एशिया में भड़कती युद्ध की लपटें इस चेहरे को और भी विशाल बना देती हैं, मानो यह फारस की कोई परी कथा हो।

दूसरा, यहूदी-विरोध। शायद यह कुछ आइवी लीग परिसरों (अमेरिका के निजी शोध विश्वविद्यालय, जो अपनी अकादमिक उत्कृष्टता, उच्च चयन-मानकों और प्रतिष्ठा के लिए विश्व स्तर पर विख्यात हैं) और लंदन की सड़कों पर ज्यादा दिखता है, लेकिन इसका एक छिपा हुआ रूप भी है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। यह तब सामने आता है, जब इस्राइल को एक 'नरभक्षी' देश बताकर उसकी निंदा की जाती है। उनकी नजर में इस्राइल एक ऐसा देश है, जो अपनी मनगढ़ंत कहानी का हवाला देकर फलस्तीनियों के खिलाफ अपने अपराधों और ईरान में अपने 'सिर काटने' के मिशन को सही ठहराता है। इस्राइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध में उतर सकता है, और जीत भी सकता है। पर, जैसा कि पहले गाजा में हुआ था, यह नैरेटिव की लड़ाई हार जाएगा। हो सकता है कि इसने ईरानी नेतृत्व को पूरी तरह तबाह कर दिया हो, जिसकी शुरुआत अयातुल्ला खामनेई से हुई। और अमेरिका व इस्राइल ने भले ही ईरानी रक्षा प्रणालियों को काफी हद तक नष्ट कर दिया हो, पर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा चार दशकों से भी अधिक समय में तैयार किया गया सैन्य-औद्योगिक ढांचा अब भी बरकरार है। फिर भी, इस्राइल यह युद्ध नहीं जीत रहा है, क्योंकि इस युद्ध को लड़ने वाला इस्राइल ऐसा देश नहीं है, जिसे अपने दुश्मनों को हराने की जरूरत है, बल्कि वह तो खुद ही चुराई हुई भूमि पर थोपा गया एक झूठ है।

तीसरा, पीड़ित का पक्ष लेते वक्त, राष्ट्रों की संप्रभुता के साथ खड़े होना और राष्ट्र-निर्माण के साम्राज्यवादी दिखावे का विरोध करना नैतिक रूप से आवश्यक है। यह उदात्त उदारवादी भावना उस दमनकारी मुल्लाशाही को भी उन लोगों के लिए स्वीकार्य बना देती है, जो अन्यथा लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के विरोध और तेल संकट से आहत, ट्रंप के दौर के बाद खंडहरों से आए वे चुनौती भरे बयान, जो अब संघर्ष-विराम का संकेत दे रहे हैं, अमेरिका-इस्राइल गठबंधन के कथित अलगाव की भावना से प्रेरित हैं। ईरान अब कोई धार्मिक-फासीवादी मुल्क नहीं रहा। वह कमजोर होने के बावजूद, एक ऐसे साम्राज्यवादी के सामने डटकर खड़ा है, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए बस एक दिखावे की आड़ ढूंढ रहा है। जीत के नारों के बीच ईरान को देखना कुछ लोगों को सुकून देता है, खासकर उन्हें, जो ट्रंप और नेतन्याहू की नीतियों को गलत मानते हैं। इसलिए अब वे चाहते हैं कि 'महान इस्लामी क्रांति' ही विजयी हो।

इस बात की संभावना कम ही है कि इन तीनों उदारवादी दृष्टिकोणों का गठबंधन ईरान को युद्ध जीतवा पाएगा। अगर ईरान ने कुछ हासिल किया है, तो वह यह है कि इसने दमन को प्रतिरोध की आड़ में छिपा दिया है। यह कुछ बेवकूफों द्वारा गढ़ा गया एक बेहतरीन कथा भ्रम है कि ईरान अब न तो 'आस्था का आखिरी साम्राज्य' रहा, और न ही 'क्षेत्रीय उथल-पुथल का केंद्र'। अब यह वह 'पुलिस राज' भी नहीं रहा, जो अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा डरता हो, और जिसकी सड़कों पर 'ईश्वर की अपनी गोलीबारी करने वाली पुलिस' तैनात रहती हो, और अब यह वह क्रांतिकारी राज्य नहीं रहा, जो शहादत की भावना का इस्तेमाल खुद मरने और लोगों को मारने के लिए करता हो। ईरान अचानक ही 'पीड़ित' होने की उस स्वायत्त स्थिति में सुरक्षित महसूस करने लगा है और उसका अस्तित्व ही इस युद्ध का एकमात्र नैतिक उद्देश्य बन गया है।

आज का इतिहास

1942 द्वितीय विश्व युद्ध-जापानी बलों ने बेटन डेथ मार्च में युद्ध शिविर के 90,000 से अधिक कैदियों को जबरन स्थानांतरित करने से पहले फिलीपींस में बाटन प्रायद्वीप पर बेटन की लड़ाई में मित्र देशों की सेना को हराया।
1948 इर्गन और लेही ज़ायोनीवादी अर्धसैनिक समूहों के लड़ाकों ने येरूशलम के पास डीर यासिन पर हमला किया, जिसमें 100 से अधिक मारे गए।
1957 मिस्र ने ब्यापार के लिए सुएज नहर को फिर से खोला गया।
1959 नासा ने प्रोजेक्ट मरक्यूरी में पहले अंतरिक्ष यात्री बुध सेवन (चित्र) के चयन की घोषणा की।
1961 यूसुफ गांड सिएरा लियोन में पहले मूल रोमन कैथोलिक पादरी के रूप में दर्जा मिला।
1963 ब्रिटिश राजनेता सर विंस्टन चर्चिल संयुक्त राज्य अमेरिका के मानद नागरिक बने।
1965 पश्चिम जर्मन संसद नाजी युद्ध अपराधों पर सीमाओं के क़ानून को बढ़ाया।
1967 पहली बोइंग 737 ने अपनी पहली उड़ान भरी, आखिरकार सबसे अधिक ऑर्डर किया गया और दुनिया भर में वाणिज्यिक यात्री जेट विमान का उत्पादन किया।
1972 सोवियत संघ और इराक ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
1988 ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री बने।
1989 एशिया की पहली सम्पूर्ण भूमिगत संजय जलविद्युत परियोजना शुरू की गयी।
1995 25 प्रदर्शनों के बाद प्लायमाउथ थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में अनुवाद बंद हो गया।
1995 59 वीं गोल्फ मास्टर्स चैम्पियनशिप: बेन क्रेंशॉ जीतता है, 274 की शूटिंग करता है।
1997 एनएफएल ने घोषणा की कि वह सीएफएल को 3 रू डॉलर और संभावित वर्ल्ड क्लासिक बाउल देगा।
1998 सऊदी अरब में मीना के पास भगदड़ में 150 से अधिक यात्रियों की मृत्यु।
1999 नाइजर के अध्यक्ष इब्राहिम बार मेन्ससारा की हत्या कर दी गई।
2002 बहरीन में निगम चुनाव में महिलाओं को हिस्सा लेने की अनुमति दी गयी।
2003 इराक गठबंधन सेना के आक्रमण ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और फिरदोस स्क्वायर में सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिरा दिया गया।
2005 चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार ने अपने लंबे समय के मालकिन पार्किंग बोल्स से शादी की।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सफलता के नित-नए आयाम स्थापित करती भाजपा

दीपक कुमार त्यागी

भारत को एक समर्थ शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्र को प्रथम मानने का दावा करने वाले राजनेताओं के एक समूह ने वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन किया था। भाजपा का गठन नई दिल्ली के कोटला मैदान में 6 अप्रैल 1980 को आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में तत्कालीन दिग्गज नेताओं की उपस्थिति किया गया था। उस वक्त भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे।

भाजपा नेतृत्व व कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं को अपनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं लोकहित के विषयों पर कांग्रेस के प्रति मुखर रहते हुए उसको जनता की अदालत में घेरकर के भारतीय लोकतंत्र में अपनी एक अलग ही विशिष्ट पहचान बनाते हुए सशक्त भागीदारी दर्ज करते हुए देश की राजनीति को नए आयाम देने का कार्य किया है। जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार के दौर के बाद से ही भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि ने दिन-रात मेहनत करके भाजपा को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक़ बनाया और भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1984 में लड़ा था, जिसमें उसने 2 सीटों पर जीती हासिल करके भाजपा ने खाता खोला था। उसके बाद भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, जिसके चलते उस वक्त भाजपा की देश के कई राज्यों में सरकार बनी और भाजपा को कल्याण सिंह जैसा फॉयर ब्रांड राजनेता मिला था। शीर्ष नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत के दम पर ही वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। जिसके बाद भाजपा ने अपनी जड़ें देश के अधिकांश हिस्सों में जमाने के लिए कार्य तेज़ी से करना शुरू किया था।

अटल युग के बाद 10 वर्ष तक केन्द्र में विपक्ष में बैठने के लंबे वनवास के बाद वर्ष 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा में यह नरेन्द्र मोदी व अमित शाह के युग जबरदस्त ढंग से प्रारंभ था। मोदी-शाह के इस दौर में भाजपा ने राजनीति के नित-नए कीर्तिमान स्थापित किए,

अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में लगभग 11 करोड़ सदस्य बनाकर के विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बनने का खिताब हासिल किया। वहीं मोदी-शाह की इस जोड़ी ने आज भी अपनी चाणक्य नीति व देश में विकास पर आधारित राजनीति की मजबूत नींव रखकर विपक्षी दलों की नींद उड़ानें का काम कर रखा है। आज देश में देश में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार और आंध्र प्रदेश में भाजपा या एनडीए सरकार हैं। देशभर में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सर्वाधिक 1654 विधायक हो गए हैं। भाजपा के पास लगभग 240 लोकसभा सांसद हैं, वहीं लगभग 106 राज्यसभा सांसद हैं। देश की राजनीति में मोदी-शाह की जोड़ी का जलवा कायम है, विपक्षी दल उनकी राजनीति की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके चलते देश के हृदय गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में भाजपा काबिज है, केन्द्र के साथ कई राज्यों में भाजपा लगातार सरकार बनाने में सफल हो रही है?।

बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश में आम लोगों को मोदी राज में विकास कार्यों का बड़ा सकारात्मक परिवर्तन धरातल पर नज़र आने लगा है। देश के विश्वस्तरीय नव निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहे हैं। मोदी सरकार एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। वह भारत को 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मोदी भारत को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे है। देश में आज भाजपा एक ऐसे प्रमुख राष्ट्रवादी दल के रूप में उभर कर सामने आ रही है जिस दल का लक्ष्य देश में सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करना है। 26 मई, 2014 को नरेन्द्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है तब से ही मोदी सरकार ने अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश में नव निर्माण के एक नए युग की शुरुआत की है। आज मोदी सरकार की नीतियां आम जनमानस के बीच लोकप्रिय हैं, मोदी सरकार की योजनाएं अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आम लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुधार से परिपूर्ण सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रही हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की देशभर में एक नयी अलख जगायी है। आम जनमानस के बीच मोदी सरकार के दौर को एक नये युग के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की मोदी सरकार सुशासन, आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता अभियान, योग के सहारे भारत को स्वथ्य बनाने का अभियान आदि से देश को एक नयी ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया आदि जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं।

वहीं राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति व पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पैठ आम जनमानस के बीच और मजबूत करने का काम किया है। भाजपा के तेजतर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर न्याय और हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्यशैली की पूरे देश में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की अदालत में यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित ओजस्वी नेतृत्व आज केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास मौजूद है।

होर्मुज पर ईरान के साथियों को खतरा नहीं भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी

पवन

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की छाया में भारत के नौवें जहाज का होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित पार होना देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के प्रति भरोसा तो जगाता ही है, लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी राहत देने वाली खबर है। गौरतलब है कि तेहरान द्वारा होर्मुज मार्ग से जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद से ही भारत अपने जहाजों के इस मार्ग से गुजरने को लेकर ईरान के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची कह भी चुके हैं कि भारत जैसे तेहरान के मित्र देशों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। ऐसे संकट के समय में, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, होर्मुज के जोखिम भरे रास्ते से तेल और गैस से भरे सबसे अधिक जहाज सुरक्षित निकालना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी कही जा सकती है। यही नहीं, 2019 के बाद यह पहली बार है, जब भारत ने ईरान से तेल व एलपीजी आयात किया है, जिसका भुगतान अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए युआन/स्थानीय मुद्राओं में करके ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

होर्मुज समुद्री मार्ग की अहमियत इससे ही समझी जा सकती है कि भारत के कच्चे तेल के आयात का करीब 40 फीसदी, एलएनजी आयात का 50 फीसदी से अधिक और एलपीजी आयात का करीब 90 फीसदी हिस्सा इसी मार्ग से ही गुजरता था। भारत की सालाना एलपीजी खपत 3.3 करोड़ टन से अधिक है, जिसमें आयात पर निर्भरता 60 फीसदी है। पिछले कुछ समय में देश में गैस-तेल

संकट के संदर्भ में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सरकार ने बेहद तनावपूर्ण वैश्विक हालात में अमेरिका व इस्राइल के साथ ही ईरान के साथ भी संबंधों को साधते हुए अपनी बहुध्रुवीय विदेश नीति का ही परिचय दिया है।

ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने भी पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कम करने में भारत की भूमिका को अहम बताया है। हालांकि, चुनौतियां अभी बाकी हैं। अगर अमेरिका व ईरान में जंग रोकने पर सहमति हो भी जाती है, तो ट्रंप की शैली को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह कितना टिकेगी। ऐसे में, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर दीर्घकालिक रणनीति अपनानी चाहिए। अच्छी बात है कि भारत ऊर्जा आयात में विविधीकरण को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन, अब समय आ गया है कि स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिले। आयात निर्भरता को कम करके ही वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों के असर को सीमित किया जा सकता है।

असम चुनाव में किसका साथ देंगे चाय बागान मजदूर

प्रभाकर मणि तिवारी

असम में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में चाय बागान मजदूर किसका साथ देंगे? मतदान से ठीक पहले राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कम से कम 35 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं। सत्ता की ओर जाने का रास्ता इन बागानों से होकर ही गुजरता है। बागान मजदूरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए सत्ता के दोनों दावेदार यानी भाजपा और कांग्रेस इनको अपने पाले में खींचने के लिए लुभावने वादे करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिछले असम दौरे के दौरान मजदूरों के साथ मिल कर पत्तियां तोड़ी थी और उनका पारंपरिक आदिवासी नृत्य देखा था।

उनके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाय बागानों का दौरा कर चुके हैं। इससे इन मजदूरों की अहमियत समझ में आती है। लेकिन आखिर यह मजदूर क्या सोच रहे हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने चाय बागान मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू करने और उनको जमीन का पट्टा देने का दावा किया है। लेकिन कई मजदूर अपना घर नहीं होने से हताश है। उनको राज्य सरकार की अरुणोदय योजना के तहत मासिक सहायता भी नहीं मिल रही है। असम चाय निगम के तहत चलने वाले सिनामारा चाय बागान की एक मजदूर सुमित्रा ओरांव बताती है कि उनको अरुणोदय योजना के तहत पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाके में पीने के पानी की दिक्कत तो है ही, कच्चे मकान में रहना भी उनकी मजबूरी है।

हालांकि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मजदूरों को मकान मिले हैं। लेकिन अब तक सबको यह नहीं मिल सका है। पूर्वी और उत्तरी असम के नौ जिलों में फैले इन चाय बागानों के करीब 35 लाख मजदूर राज्य की 126 में से 35 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। यही वजह है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अचानक मजदूरों के प्रति हमदर्दी दिखाने लगी है। सरकार ने बागान मजदूरों को पांच-पांच हजार की वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ

ही उनकी दैनिक मजदूरी भी 30 रुपए बढ़ा दी है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी के बागानों में यह रकम 280 रुपए प्रति दिन हो गई है। इस बार बीजेपी ने अगले पांच साल में इस रकम को बढ़ा कर पांच सौ करने का वादा किया है।

लेकिन मजदूरों में अब भी इस बात की नाराजगी है कि पार्टी ने वर्ष 2014 के चुनाव से पहले किया गया अपना एक वादा अब तक पूरा नहीं किया है। वह है इन मजदूरों को अनुसूचित जनजाति के दर्जे का। पार्टी लगभग हर चुनाव में यह वादा करती रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि कांग्रेस ने छह दशक में बागान मजदूरों के लिए जितना काम नहीं किया उतना बीजेपी सरकार ने दस साल में कर दिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस महज वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल करती रही है।मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार इन मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से गंभीरता से बातचीत कर रही है।

लेकिन मजदूरों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद ही आदिवासी के तौर पर उनका वजूद सुरक्षित हो सकता है। उनका सवाल है कि आखिर सरकार को इसमें 12 साल से ज्यादा का समय क्यों लग रहा है जबकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है? असम में डिब्रूगढ़ से जोरहाट तक साढ़े आठ सौ से ज्यादा चाट बागान हैं। वर्ष 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की ज्यादातर सीटों पर भाजपा उम्मीदवार ही विजयी रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस महीने की पहली तारीख को डिब्रूगढ़ के पास मनोहारी चाय बागान का दौरा कर पत्तियां चुनी और मजदूरों से बातचीत की। उसके कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी नाजिरा में एक चाय बागान में रैली को संबोधित किया। दो अप्रैल को राहुल गांधी और गौरव गोगोई भी टीटाबोर में एक चाय बागान में रैली कर चुके हैं।

भाजपा इन इलाकों में बीते एक दशक में शुरू की गई अपने कल्याण योजनाओं का प्रमुखता से प्रचार कर रही है। उसका दावा है कि इन योजनाओं के कारण बागान मजदूरों का जीवन स्तर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इन योजनाओं से जमीनी स्तर पर तस्वीर नहीं बदली है। बागान मजदूर अब भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में बागान मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और नई योजनाओं के साथ इस उद्योग की बेहतरी की दिशा में ठोस कदम उठाने का वादा किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की वजह से इस बार निचले और मध्य असम में मुस्लिम वोटरों के कांग्रेस के पक्ष में मतदान की संभावना को ध्यान में रखते हुए पार्टी चाय बागानों पर खास ध्यान दे रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस का सवाल है कि आखिर बीजेपी बागान मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर सकी है? पार्टी के नेता गौरव गोगोई का आरोप है कि चाय बागानों में पीने के पानी के साथ ही स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई बागान बंद हो गए हैं और वहां रहने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मजदूरों की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग पुरानी है। 2016 तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इसके कारण इस बार मजदूरों को उसके पक्ष में झुकने की संभावना कम ही है।

तमिलनाडु में पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला

आर राजगोपालन

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चूंकि मतदान का दिन है, इसलिए राज्य में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है और अगले दो सप्ताह के लिए उग्र भाषण और रोड शो मतदाताओं को उत्साहित करेंगे। इस बार का चुनावी मुकाबला कठिन है और बताया जा रहा है कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के इस बार के परिणाम एक नया राजनीतिक आश्चर्य और अप्रत्याशित मोड़ पेश करें, तो हैरानी नहीं होगी। छह लाख मतदाताओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का एक नया स्वरूप सामने आ सकता है। हालांकि प्री-पोल सर्वे में द्रमुक गठबंधन को जीतता दिखाया जा रहा है। कुल 21 राजनीतिक दलों ने लगभग 2,200 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

अभी तक तमिलनाडु में बारी-बारी से द्रमुक या अन्नाद्रमुक की सरकार रही है। लेकिन इस बार चुनावी सभाओं में विपक्षी दलों के लिए भारी भीड़ है। अन्नाद्रमुक, विजय की टीवीके और सीमन की एनटीके की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। द्रमुक नेताओं को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। एमके स्टालिन की द्रमुक को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में प्राथमिक चुनावी मुद्दा 'ड्रग्स' है। द्रमुक को छोड़ सभी राजनीतिक दल अवैध शराब, विदेशी शराब के प्रवाह, विश्वविद्यालयों में बलात्कार और खराब कानून-व्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चुनावी फंडिंग और देर रात मतदाताओं को नकदी वितरण जैसे बाहरी कारक भी प्रभावी हैं। घोषणापत्र मजाक बनकर रह गये हैं। किशोरों और छात्रों के लिए फ्रिज, लैपटॉप, ग्राइंडर, व्हीलचेयर, वाइफाइ और मुफ्त इंटरनेट का वादा किया जा रहा है।

अन्नाद्रमुक और टीवीके के साथ द्रमुक मुफ्त उपहारों की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। पहली बार लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन सभी दलों को वित्तपोषित कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां हैं कि 'हर जगह मार्टिन है'। सैंटियागो मार्टिन की पत्नी लीमा अन्नाद्रमुक पर दांव लगा रही हैं, बेटा चार्ल्स एलजेके में किस्मत आजमा रहा है, जबकि दामाद टीवीके के साथ हैं। तमिल समाचार चैनल अन्नाद्रमुक, भाजपा, टीवीके और द्रमुक की रैलियों का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जबकि पहले ये चैनल द्रमुक का गुणगान करते थे। हालांकि, अब जनता सोशल मीडिया और यूट्यूब लाइव रिपोर्टिंग की ओर मुड़ गयी है। यह तमिलनाडु में एक नया मोड़ है। एआइ

द्वारा निर्मित नकली वीडियो और वास्तविक लगने वाली ऑडियो क्लिप अन्नादुरई, कामराज, एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि के नाम पर हलचल मचा रहे हैं।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक की जड़ें तमिलनाडु के हर गांव में हैं, पर भाजपा या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों की स्थिति ऐसी नहीं है। इस बार टीवीके जैसी नयी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। तमिल सिनेमा के एक 'सुपर हीरो' जोसेफ विजय इसके प्रमुख हैं, जिन्हें 'थलपति' कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार तमिलनाडु चतुष्कोणीय मुकाबले का सामना कर रहा है और ऐसे मुकाबले में जीत का अंतर 1,000 वोटों से भी कम रहे, तो आश्चर्य नहीं होगा। विजय के प्रवेश से राज्य के ईसाइयों को एक रणनीतिक बल मिला है और पहली बार अल्पसंख्यक वोट द्रमुक से हटकर टीवीके की ओर जा सकते हैं। विजय के विशाल सिनेमाई प्रशंसकों के कारण टीवीके छह लाख मतदाताओं में से 20-25 फीसदी पर कब्जा कर सकती है। हालांकि प्री-पोल सर्वे में बताया गया है कि विजय की पार्टी आठ से 10 सीटें जीत सकती है। गौरतलब है कि 1990 के दशक से विजय के फैन क्लब की 5,000 शाखाएं स्थापित हैं।

द्रविड़ भूमि में मोदी-अमित शाह की जोड़ी के कारण भाजपा को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, जिससे एनडीए के अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी को लाभ होने की उम्मीद है। जयललिता के जीवनकाल में ही अन्नाद्रमुक के चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर के लिए भाजपा के एजेंडे का उल्लेख किया गया था। जयललिता ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग भी लिया था। तमिलनाडु में 'कमल' का चुनाव चिह्न लोकप्रिय है। हालांकि निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के चार ही विधायक थे। इस चुनाव में भाजपा विधायकों का आंकड़ा कितना रहता है, यह देखने वाली बात होगी।

दूसरी तरफ, तमिलनाडु में कांग्रेस न सिर्फ एक जानी-पहचानी पार्टी है, बल्कि द्रमुक गठबंधन में इसकी मौजूदगी धर्मनिरपेक्ष वोट हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात यह है कि विजय द्वारा टीवीके लॉन्च करने और करूर रैली में भगदड़ में 41 मौतों के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के टीवीके के करीब आने से राजनीतिक परिदृश्य बदला है। राहुल गांधी पिछले छह महीनों से टीवीके के करीब आने के इच्छुक थे, पर द्रमुक ने इसे भांप लिया। फिर सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से स्टालिन ने कांग्रेस को द्रमुक के नये गठबंधन 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' (एसपीए) से बाहर जाने से रोक दिया। एनटीके के नेता सीमन लिट्टे नेता प्रभाकरण के पुराने समर्थक हैं, जो तमिल ईलम का मुद्दा उठाते हुए अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास उन आठ प्रतिशत लोगों का वोट बैंक है, जो तमिल राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। द्रमुक इस चुनाव में मुख्यमंत्री स्टालिन के पांच साल के कार्यकाल पर वोट मांग रही है।

द्रमुक अपने कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु वितरण और अपने घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल को अपनी उपलब्धि बता रही है। हालांकि सत्ता विरोधी लहर के साथ आर्थिक चिंताएं तथा कानून-व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी हमले इस चुनाव में द्रमुक की कड़ी परीक्षा लेंगे। द्रमुक के चुनावी भाषणों में ज्यादातर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आलोचना होती है। स्टालिन की रणनीति अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने की है। द्रमुक का मानना है कि ईसाई वोटों के अलावा मुस्लिम मतदाता भी विजय की ओर झुक सकते हैं। पिछले चुनावों में जब मुकाबला मुख्य रूप से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच था, तब ईसाइयों और मुसलमानों के वोट ने जीत में निर्णायक भूमिका निभायी थी। पर टीवीके की अभी शुरुआत ही होने और 'जोसेफ' विजय के ईसाई टैग से मुस्लिम वोटों के एक हिस्से के उससे छिटकने की उम्मीद है। चूंकि अल्पसंख्यक वोटों के द्रमुक और टीवीके के बीच बंटने की संभावना है, इसलिए हिंदू वोटों के, जिनमें कोनार, मुक्कुलाथोर, मुथराय्यार और अनुसूचित जाति के समुदाय शामिल हैं, चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। अलबत्ता आप इसे किसी भी नजरिये से देखें, तमिलनाडु के चुनाव परिणाम निष्पक्ष और हिंसा मुक्त होंगे। यही तो लोकतंत्र की खासियत है।

असल समस्या ट्रम्प हैं या दुनिया का दरोगा बनने की अमेरिकी मनोदशा?

रहीस सिंह

खबरें बता रही हैं कि अमेरिका गुस्से में है। सड़कों पर एक आवाज सुनाई दे रही है- 'नो किंग्स'। यह आवाज अमेरिकी शहरों से भी और आगे बढ़कर दुनिया के दूसरे देशों के शहरों- पेरिस, लंदन, बर्लिन, रोम, एथेंस और लिस्बन तक में भी सुनाई दी। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह का प्रदर्शन राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ असंतोष की अभिव्यक्ति है अथवा अमेरिकियों में गहरे तक पैठी हुई निराशा और बेचैनी से हुआ विस्फोट है? क्या इसके जरिए यह बताने की कोशिश हो रही है कि ट्रम्प अमेरिका नहीं हैं, जैसा कि उन्हें पेश करने की कोशिश की जा रही है या वे खुद को पेश कर रहे हैं? एक सवाल और, क्या अमेरिका वैसा ही है जैसा कि अमेरिकी मानते आ रहे हैं? यह तो पता नहीं कि अमेरिका सहित दुनिया में 'नो किंग्स' प्रदर्शन ट्रम्प के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं अथवा नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रम्प अब अमेरिका के लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं। यह 'नो किंग्स' प्रदर्शन का तीसरा संस्करण था जो 3000 से अधिक जगहों पर हुआ जो यह संदेश देने में सफल हो रहा है कि यह किसी नेता के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो सत्ता को जनता से ऊपर समझने की गलती कर रही है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अमेरिकी मनोविज्ञान को समझना जरूरी लगता है। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि अमेरिका में पिछले एक दशक से या उससे भी कुछ पहले से जो उथल-पुथल हो रही है वह अमेरिकियों के लिए गर्व का प्रश्न है अथवा निराशा का? एक लेखिका लिडिया पोलग्रीन अपने एक लेख में लिखती हैं कि कभी-कभी मुझे लगता है कि अमेरिका में जो कुछ घटा है, उसने उस राष्ट्र को पूरी तरह बदल दिया है जिसे मैं जानती थी। फिर भी, हर संकट के बाद मुझे यह अहसास होता है कि शायद अमेरिका वैसा कभी था ही नहीं जैसा हम समझते रहे। वे आगे लिखती हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का उदय प्राय: अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक असाधारण विचलन के रूप में देखा जाता है, एक ऐसे विचित्र अपवाद के रूप में जो हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाता। लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। ट्रम्प केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वे उस लंबे ऐतिहासिक प्रवाह का बाइ-प्रॉडक्ट हैं, जिसने अमेरिका की राजनीति, समाज और वैश्विक भूमिका को आकार दिया है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? यह प्रश्न इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ट्रम्प या उन जैसा नेतृत्व किसी देश को तब तक अपने नियंत्रण में नहीं ले पाता जब तक कि उसे स्वीकारने की मनोदशा निर्मित न कर ले। वैसे अमेरिका का इतिहास स्वयं को असाधारण मानने की धारणा से कभी उबर नहीं पाया। कारण यह कि अमेरिका खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ और दुनिया का पथप्रदर्शक मानता है। उसकी यही सोच पढ़े-लिखे अमेरिकियों को भी उन कमियों से आंखें मूंद लेने पर मजबूर करती रही जो देश और उसके नागरिकों के हित में नहीं थीं। इसके विपरीत वे अमेरिकी संस्थाओं की मजबूती और अपने लोकतंत्र पर इतराते रहे। जबकि सच यह है कि अमेरिका हमेशा से विरोधाभासों से भरा रहा है। वह स्वतंत्रता और असमानता, लोकतंत्र और बहिष्कार, आदर्शवाद और शक्ति आधारित राजनीति (पावर पॉलिटिक्स) के बीच झूलता हुआ आगे बढ़ा। ट्रम्प इसी विरोधाभास से उपजे हैं। किसको नहीं पता कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने खुद को स्वतंत्रता का वैश्विक रक्षक घोषित किया था। लेकिन क्या वह सच में ऐसा ही रहा? यदि हां तो उन युद्धों और हस्तक्षेपों को कहां रखा जाए जिनके परिणाम विनाशकारी रहे। वियतनाम से लेकर इराक और काबुल से लेकर बेरूत तक, पूरी दुनिया में शक्ति के प्रयोग प्राय: उन आदर्शों से टकराते हुए देखे गए जिनका अमेरिका दावा करता आ रहा था। फिर ट्रम्प पर विलाप या गुस्सा क्यों? ट्रम्प ने तो उन संदेहों को केवल गहरा किया है जो राजनीति में पहले से ही मौजूद थे। असल समस्या तो उस अमेरिकी व्यवस्था और चरित्र में ही निहित है जिसे उसने कम से कम पिछली एक सदी के दौरान विकसित किया। अमेरिका की विदेश नीति के मूल में यह विचारधारा रही है कि उसे दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। बिना भय और युद्ध के यह संभव ही नहीं।

14 को खरमास खत्म फिर गूंजेगी शहनाइयां

19 अप्रैल को पहला विवाह मुहूर्त

14 अप्रैल को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद से फिर शादियों का दौर शुरू हो जाएगा। खरमास खत्म होते ही विवाह, देव प्रतिष्ठा, नूतन गृह निर्माण, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य 14 अप्रैल के बाद शुरू हो गए हैं। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 15 मार्च से लगे खरमास की समाप्ति 14 अप्रेल को रही है। जिसके बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास यानी मीन महीना खत्म हो गया है। इससे पहले 15 मार्च को सूर्य के मीन राशि में आने के बाद मीन मास चल रहा था। खरमास होने के कारण पिछले एक महीने से हर तरह के मांगलिक कामों पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अब इनके लिए मुहूर्त रहेंगे। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब सूर्य मीन राशि में रहता है तब इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए। इस दौरान सिर्फ जप, तप और स्नान-दान करना चाहिए। खासकर 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त है, जिसमें बिना पंचांग देखे विवाह किए जा सकते हैं। मई का महीना भी शादियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान गुरु और शुक्र की स्थिति अनुकूल रहने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

14 अप्रैल 2026 सेविवाह का मौसम पुनः शुरू हो जाएगा, जो चातुर्मास के प्रारंभ तक जारी रहेगा। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है और इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को और देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को पड़ेगी। इसलिए, 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे।

19 अप्रैल से 29 जून तक विवाह के लिए कुल 24 मुहूर्त हैं। अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है।

17 मई से 15 जून तक अधिक मास

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, जिसके चलते करीब एक माह तक विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। इसी कारण अक्षय तृतीया से पहले और इसी दिन बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन तीन माह में विवाह समारोहों की भरमार रहेगी।

गृह प्रवेश विवाह और शुभ काम

खरमास यानी मीन मास खत्म हो जाने से 16 संस्कार और अन्य शुभ काम किए जा सकते हैं। शुभ मुहूर्त और शुभ दिन में अन्नप्राशन, नामकरण, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ और अन्य शुभ काम किए जा सकते हैं। सूर्य के मेष राशि में आते ही गृह प्रवेश और विवाह के भी मुहूर्त रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति भी खुद की राशि यानी मीन में आ गए हैं। जिससे हर मांगलिक कामों में गुरु का बल और बढ़ जाएगा।

14 अप्रैल से शुरू होंगे शुभ कार्यक्रम

14 अप्रैल को होने वाली मेष संक्रांति सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है। यह नए मंगल कार्यों की शुरुआत का संकेत है। जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है और विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार जैसे आयोजनों की शुरुआत फिर से हो सकती है। आप भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो अब समय आ गया है कि आप भी इन तिथियों में अपना मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं।

डॉ. अनीष व्यास
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान,जयपुर-जोधपुर
मो.9460872809

विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त को शुभ माना जाता है। अगर किसी के विवाह की तारीख नहीं निकल पा रही है या फिर किसी कारण से शुभ मुहूर्त वाले दिन विवाह करना संभव ना हो तो अबूझ मुहूर्त में भी विवाह किया जा सकता है। धर्मग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और देव प्रबोधिनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त माना गया है।

विवाह का धार्मिक महत्व

सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कई प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं से समृद्ध है। इस परंपरा में से एक शुभ विवाह भी है, यह जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है। विवाह कई तरह से किए जाते हैं, प्रत्येक के अपने-अपने रीति-रिवाज और महत्व होते हैं। हिंदू धर्म में यह 16 संस्कारो मे से एक होता है और इसके बगैर कोई भी व्यक्ति ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है।

वर्ष 2026 के शुभ मुहूर्त

अप्रैल 2026 - 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल

मई 2026 - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 मई

जून 2026 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 जून

जुलाई 2026 - 1, 6, 7, 11 जुलाई

नवंबर 2026 - 21, 24, 25 और 26 नवंबर

दिसंबर 2026 -2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर

(कुछ पंचांग में भेद होने के कारण तिथि घट बढ़ सकती है और परिवर्तन हो सकता है।

कल वैशाख मास की कालाष्टमी जानें मुहूर्त और पूजा विधि

वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि आरंभ	9 अप्रैल, गुरुवार को रात में 9 बजकर 19 मिनट पर।
वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि समाप्त	10 अप्रैल, शुक्रवार को रात के 11 बजकर 15 मिनट पर।
वैशाख मास कालाष्टमी	10 अप्रैल, शुक्रवार (उदया तिथि के अनुसार)

वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव की विधि-विधान से पूजा की जाती है। कालाष्टमी को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक कालभैरव भगवान की पूजा करने से जातक के जीवन से भय दूर हो सकता है। साथ ही कालाष्टमी का व्रत करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है।

पंचांग के अनुसार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 9 अप्रैल, गुरुवार के दिन रात में 9 बजकर 19 मिनट पर होगा। वहीं, अगले दिन यानी 10 अप्रैल, शुक्रवार को रात के 11 बजकर 15 मिनट तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 10 अप्रैल के दिन कालाष्टमी का व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा। क्योंकि शास्त्रों में उदया तिथि में ही भैरव अष्टमी का व्रत करने का विधान बताया गया है।

कालाष्टमी 2026 व्रत और पूजा मंत्र

व्रत का मंत्र- अतिक्रूर महाकाय कल्पान्त दहनोपम,
भैरव नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि।
ओम भयहरणं च भैरवः।
ओम भ्रं कालभैरवाय फट।
ओम कालभैरवाय नमः।
ओम ह्रीं बं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरूकुरू बटुकाय ह्रीं।

वैशाख मास कालाष्टमी पूजा विधि

कालाष्टमी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही, व्रत का संकल्प अवश्य लें।

घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर बाबा काल भैरव, शिवजी और मां पार्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।

पूजा घर में चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करें और फिर, भगवान को ताजे पुष्पों की माला अर्पित करें। इसके बाद, नारियल, इमरती, गेरुआ, मदिरा आदि चढ़ाएं।

पूजा में एक चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और कुमकुम या हल्दी से भगवान का तिल करें। अब धूप-दीप दिखाकर विधि-विधान से पूजा करें।

भगवान शिव, माता पार्वती और बाबा काल भैरव की एक-एक करके आरती करें। साथ ही, पूजा में भगवान कालभैरव के मंत्रों का 108 बार जाप भी अवश्य करें।

इस दिन शिव चालीसा और भैरव चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही, आप बटुक भैरव पंजर कवच का पाठ कर सकते हैं।

कालाष्टमी के दिन रात में काले तिल, दीपक, सरसों का तेल आदि से कालभैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही, रातभर जागरण करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है।

सुहागिन महिलाएं अपनी ये पांच चीजें साझा करने से रूठ जाता भाग्य

सुहागिन महिलाओं के लिए 'सुहाग का सामान' केवल शृंगार मात्र के लिए नहीं होता, बल्कि उनके वैवाहिक सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। हिंदू धर्म में दान को 'महापुण्य' बताया गया है। लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जो पुण्य के स्थान पर आपको परेशानियां दे सकती हैं। लोक परंपराओं के अनुसार, सुहाग के कुछ सामान को दूसरों के साथ साझा करने से सुहागिन महिला को अपने निजी जीवन कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ सकता है।

सौभाग्य की सबसे बड़ी निशानी

एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर, सौभाग्य और सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। एक केवल एक शृंगार नहीं है, बल्कि पति की लंबी उम्र और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में भूलकर भी कभी दूसरी महिला को अपनी उपयोग की गई सिंदूर की डिब्बी या अपना लगाया हुआ सिंदूर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि सिंदूर साझा करने से आप अपने दांपत्य जीवन की सकारात्मकता और सौभाग्य को भी दूसरों को दे देते हैं, जिससे रिश्तों में अनबन हो जाती है।

वैवाहिक जीवन में आएंगी बाधाएं

मंगलसूत्र भी एक विवाहित स्त्री के लिए सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मंगलसूत्र एक सुहागिन की सकारात्मक ऊर्जा को संचित करता है।

ऐसे में कभी भूल से भी अपना पहना हुआ मंगलसूत्र कभी दूसरों को पहनने के लिए न दें, चाहे वह आपके कितना ही करीब क्यों न हो। क्योंकि ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकता हैं।

भाग्य पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

हिंदू धर्म में सुहागिन के माथे की बिंदी भी सौभाग्य और सुहाग की निशानी के रूप में देखी जाती है।

अक्सर महिलाएं अपनी लगाई हुई बिंदी किसी और को दे देती हैं या फिर किसी दूसरी महिला की इस्तेमाल की हुई बिंदी खुद लगा लेती हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया। ऐसा करने से आपके भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

न साझा करें ये चीजें

ज्योतिष शास्त्र में सुहागिन महिला द्वारा पैरों में पहने जाने वाले बिछिया और पायल का संबंध 'शुक्र' से माना गया है, जो सुख-सुविधाओं के कारक हैं। इसलिए इन्हें उतारकर किसी को दे देने का अर्थ है कि आप अपने सौभाग्य का भी दान कर रही हैं।

इससे न केवल रिश्तों में खटास आती है, बल्कि परिवार को आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही एक सुहागिन स्त्री को अपनी चूड़ियां भी किसी दूसरों को उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। इससे भी आपके सौभाग्य पर बुरा असर पड़ता है।

शनि उदय मीन राशि में, 12 को हो सकता है वृषभ, मिथुन समेत पांच राशियों की लाइफ में बड़ा बदलाव

शनि का उदय गुरु की राशि मीन में 12 अप्रैल, रविवार के दिन होने जा रहा है। शनि के उदित होने से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ राशियों को लाभ मिलता है, तो कुछ जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। पंचांग दिवाकर के अनुसार, शनि मीन राशि में 8 मार्च, रविवार से अस्त चल रहे थे। वहीं, अब 12 अप्रैल को करीब सुबह 5 बजे मीन राशि में उदित होंगे। इसके प्रभाव से वृषभ, मिथुन सहित 5 राशियों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सामाजिक दायरा बढ़ने के भी संकेत हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि शनि उदय किन-किन राशियों के लिए शुभ रहेगा।

वृषभ राशि : आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे

शनि उदय वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है। इसके प्रभाव से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपको जिन विषयों में अधिक रुचि है उनके बारे में गहराई से जानने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ने से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शनि का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। घर-परिवार के मामले में भाइयों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।

मिथुन राशि : विशेष सम्मान या पुरस्कार मिलने के संकेत

आपके कर्म भाव यानी दसवें भाव में शनि का उदय होगा। यह मिथुन राशि के जातकों को अधिक मेहनत और योजनाओं के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेहनत तो करनी होगी वहीं, साथ-साथ सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। आपको किसी अच्छे मार्गदर्शक का सहयोग मिलेगा। वहीं, किसी सम्मान और पुरस्कार मिलने के संयोग है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। साथ ही, किसी शुभ काम में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा क्योंकि, खर्चे बढ़ने के संकेत हैं। इस समय छोटी अवधि के निवेश की बजाए बड़ी अवधि के निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा।

तुला राशि : बैंकिंग संबंधी कार्यों में लाभ होगा

शनि उदय तुला राशि के छठे भाव में होने जा रहा है। शनि आपकी राशि के लिए योगकारक ग्रह हैं। ऐसे में उनका उदय होना आपके कार्यक्षेत्र के लिए शुभ रहेगा। बैंकिंग से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। अगर लोन से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था तो उसकी बाधा भी दूर हो सकती है। यदि किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि, पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। तनाव और घरेलू खर्च बढ़ने के संकेत बने हुए हैं। इस समय वाद-विवाद की स्थिति से स्वयं को दूर रखें। अनचाहे यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है।

धनु राशि : घर या वाहन खरीद सकते हैं

आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का उदय होगा। इसके प्रभाव से धनु राशि की वाणी और संचार कौशल में बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे तो अब राहत मिल सकती है। साथ ही, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने के भी योग हैं। घर या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। रिनोवेशन के कार्य में भी आप अपने पैसा लगा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। हालांकि, काम का प्रेशर भी बना रह सकता है जिसके चलते आपको अधिक मेहनत करनी होगी। वहीं, कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।

मकर राशि : प्रबंधन क्षमता से फायदा मिलेगा

शनि का उदय मकर राशि के तीसरे भाव में होने जा रहा है। जो आपके लिए शुभ हो सकता है। इसके प्रभाव से सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। सामाजिक नेटवर्क बेहतर होने से फायदा मिलने के योग हैं। कारोबार के क्षेत्र में साहसिक फैसले ले सकते हैं। वहीं, प्रबंधन क्षमता का भी आपको फायदा मिलने के संकेत हैं। परिवार में भाई और बहनों का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मानसिक भटकाव रह सकता है। वहीं, जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें अब सफलता मिल सकती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गुजरात पर विवादित बयान को लेकर खरगे ने अब जताया खेद

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि वे गुजरात के लोगों का अत्यंत सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनका यह स्पष्टीकरण केरल विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते विवाद के बीच आया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि केरल में दिए गए मेरे हालिया चुनावी भाषण में कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी, मैं इसके लिए हार्दिक खेद व्यक्त करता हूं। मेरा इरादा कभी भी गुजरात के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, जिनके लिए मेरे मन में हमेशा से सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग में टीएमसी का हाई-वोल्टेज ड्रामा

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल और भारत निर्वाचन आयोग के बीच बुधवार को हुई बैठक तनावपूर्ण हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें आई। सूत्रों के अनुसार, चर्चा जल्द ही गरमागरम बहस में बदल गई। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कथित तौर पर बैठक के दौरान चिल्लाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जवाब न देने के लिए कहा। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बार-बार पत्र भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। ओ%ब्रायन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैठक के सात मिनट के भीतर ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे क्या कहा- चले जाओ। हम संसद में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। सूत्रों ने आगे दावा किया कि बैठक सात मिनट के भीतर ही समाप्त कर दी गई, और अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रतिनिधिमंडल को बैठक छोड़ने के लिए कहा।

39 दिन की जंग से अमेरिका को क्या मिला: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर निराशा व्यक्त की, जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह मार्ग पहले से ही सभी के लिए खुला था और उन्होंने संघर्ष के परिणाम को लेकर अमेरिका पर सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तो क्या युद्धविराम से एक जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है, एक ऐसा जलडमरूमध्य जो युद्ध शुरू होने से पहले सभी के लिए खुला और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था? इस 39 दिन के युद्ध से अमेरिका को आखिर क्या हासिल हुआ? बुधवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर बमबारी और हमले के अभियान को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की और दो सप्ताह के लिए द्विपक्षीय युद्धविराम का प्रस्ताव रखा। ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि ईरान द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्री प्रस्ताव व्यवहार्य है।

परिसीमन प्रक्रिया पर सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को घेरा

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में जनसंख्या परिवर्तन के अनुरूप लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन शामिल है। दक्षिणी राज्यों में भाजपा विरोधी दलों ने इस प्रस्तावित कदम पर आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने वाले दक्षिणी क्षेत्र को संसदीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव में कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि देश के अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को इसका काफी लाभ होगा। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार की भाजपा परिसीमन प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रही है, जबकि उसे इसे पूरा करने के अपने इरादे स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है? 2001 में, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राष्ट्रीय हित में परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था।

डीएमके सरकार से त्रस्त हो गई जनता : पलानीस्वामी

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने वेलाचेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से इसे सत्ता से हटाने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को फेल मॉडल करार देते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में डीएमके शासन के दौरान लोगों ने काफी मुश्किलें झेली हैं और अब समय आ गया है कि इस बुरे शासन को हटाया जाए। उन्होंने अपनी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि एआईएडीएमके सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था मजबूत रही और आम लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई करती थी।

केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव आज

नईदिल्ली। देश के तीन राज्यों असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल गुरुवार को सुबह 7 बजे से एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। असम में 126 सीट, केरल में 140 और पुदुचेरी में कुल 30 सीटें हैं। असम में 2.50 करोड़ मतदाता व 722 उम्मीदवार हैं। केरल में 890 उम्मीदवार व 2.71 करोड़ मतदाता हैं। वहीं, पुदुचेरी में कुल 294 उम्मीदवार हैं। यहां 9.44 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

असम में, हिमंत बिस्वा सरमा को पूरा भरोसा है कि वह भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाएंगे और खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक आधार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस का संगठन राहुल गांधी की उस पसंद के कारण लड़खड़ा गया है, जिसमें उन्होंने एकमात्र गौरव गोगोई को ही असम में पार्टी की किस्मत का फैसला करने वाला बना दिया था। असम में अवैध प्रवासन ने वहां की मूल गैर-मुस्लिम आबादी के मन में गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर, हिमंत ने जमीनी स्तर पर कई मोर्चों पर विकास करके अपना काम बखूबी निभाया है। इनमें कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं को नकद आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। कांग्रेस पिछले एक दशक से विपक्ष में है, जबकि भाजपा लगातार दो बार सत्ता का सुख भोग चुकी है। चुनावी चर्चा एक बार फिर जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठिये जैसे वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित हो गई है और कांग्रेस असम के बहुसंख्यक लोगों की चिंताओं को समझने में नाकाम रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 93 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। यही नहीं, 2014 के बाद से भाजपा ने असम में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं हारा है। ऐसे में, मौजूदा माहौल को देखते हुए पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की मजबूत दावेदार नजर आ रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई वही नेता थे, जिन्होंने कभी राज्य में कांग्रेस को दोबारा मजबूती से खड़ा किया था। 2001 से 2016 तक मुख्यमंत्री रहते हुए वह असम के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बने। उनके ही एक करीबी हिमंत अब भाजपा का चेहरा हैं और उन्होंने गौरव के लिए चुनौती को इतना मुश्किल बना दिया है कि गौरव असम के बहुसंख्यक लोगों को अपने पक्ष में करने में नाकाम रहे हैं।

केरल में 81 वर्षीय पिनाराई विजयन अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचते हैं, तो वह देश में मार्क्सवादी पार्टी की एकमात्र सरकार को बचा सकेंगे। हालांकि, उनके नेतृत्व में, सत्ताधारी वामपंथी दल पिछले साल के स्थानीय निकाय चुनावों में फीके प्रदर्शन के बाद अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष ही कर रहा है। केरल को कम्युनिस्टों का आखिरी गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2018 में त्रिपुरा में सत्ता गंवाने और 2011 में अपने पुराने गढ़ पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हाशिये पर चले जाने (एक भी विधायक न होने) के बाद यही एकमात्र राज्य बचा है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, जबकि भाजपा भी राज्य में तीसरी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है।

विजयन की मुश्किलों के तार खुद उनकी पार्टी सीपीआई (एम) के भीतर ही देखे जा सकते हैं। कई मार्क्सवादी दिग्गज उनके काम करने के तरीके से नाखुश हैं और उन पर वामपंथ के 'मूल सिद्धांतों' को कमजोर करने व पिछले दस वर्षों में व्यापार और व्यवसायों के प्रति अधिक मित्रवत होने का आरोप लगाते हैं। उन पर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर झुकाव का आरोप भी लग रहा है।

विजयन अपने चुनावी अभियान में साफ तौर पर 'विकास' (विकासनम) को ही सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में केरल ने कई कठिन दौरों का मजबूती से सामना किया है- चाहे वह 2018 की विनाशकारी बाढ़ हो या कोविड महामारी का दौर। साथ ही, उन्होंने पूरे राज्य में बड़ा आर्थिक बदलाव लाया है और कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिये गरीब तबके का भी ख्याल रखा है। वहीं, कांग्रेस ईसाइयों के बीच अपने मजबूत आधार पर दांव लगा रही है, जिनकी आबादी में हिस्सेदारी 18.38 प्रतिशत है। साथ ही, राहुल गांधी के जोरदार चुनावी प्रचार के चलते कांग्रेस को उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता, जो करीब 26.56 प्रतिशत हैं, इस बार वामपंथियों से दूरी बनाकर यूडीएफ के साथ आएंगे, क्योंकि यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) एक अहम साझीदार है। दूसरी ओर, भाजपा के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यह होगी कि राज्य के हिंदू मतदाता एकजुट होकर उसके पक्ष में वोट करें। अगर ऐसा होता है, तो भाजपा इतनी सीटें हासिल कर सकती है कि वह सत्ताधारी एलडीएफ और पिनाराई विजयन के सामने मजबूती से उभर सके। हालांकि, इसकी संभावना कम ही है, फिर भी, भाजपा केरल में ईसाई समुदाय के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क बना रही है। उसने बीडीजेएस, ट्वेंटी-20 पार्टी, केरल कांग्रेस (डेमोक्रेटिक), केरल कामराज कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पक्का कर लिया है।

केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में सारा दारोमदार 75 साल के नटेसन कृष्णसामी गौंडर रंगास्वामी पर है, जिन्हें आम तौर पर 'एनआर' के नाम से जाना जाता है। वह मई 2021 से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इससे पहले वे 2001 से 2008 तक और 2011 से 2016 तक भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रंगास्वामी अपनी खुद की पार्टी, 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (एआईएनआरसी) के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का गठन 2011 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किया गया था। वह 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' (एनडीए) का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें भाजपा एक अहम सदस्य है। उनके विरोधी कांग्रेस (उनकी पुरानी पार्टी) और द्रमुक ने मिलकर चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाया था। लेकिन, विपक्ष के इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात पर दोनों पार्टियों के बीच की आपसी खींचतान की वजह से यह गठबंधन अब टूटा हुआ-सा नजर आ रहा है। नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने अलग-अलग प्रचार किया।

इस केंद्रशासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, जिन्हें उनकी अपनी ही पार्टी ने किनारे कर दिया है, ने कहा है कि कांग्रेस में उनके अपने ही साथियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के साथ रिश्तों में तनाव होने के बावजूद, रंगास्वामी मतदाताओं के साथ अपने सीधे जुड़ाव की वजह से इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल

युवाओं के आत्मनिर्भर का सपना हुआ साकार: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की 11वीं वर्षगांठ पर इसके प्रभाव की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देने और देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण रही है। ङ्क पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सही अवसर प्रदान करना व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। उन्होंने लिखा कि ठीक 11 साल पहले, आज ही के दिन शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बेहद मददगार साबित हुई है। इस योजना की सफलता दर्शाती है कि सही अवसर मिलने पर व्यक्ति न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकता है। आत्मज्ञान शुरुआत है, और धैर्य धर्म की दृढ़ता है।

मोदी ने आगे कहा कि जो विपत्तियों से विचलित नहीं होता, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया और बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 58 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे देश भर में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को मजबूती मिली है। शाह ने कहा कि इस योजना ने वित्त तक पहुंच में सुधार करके छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप और युवाओं को सशक्त बनाया है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर, स्वरोजगार और लघु उद्योगों को नई शक्ति प्रदान की गई है। इन 11 वर्षों में, इस कल्याणकारी योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 58 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे 12 करोड़ युवाओं को लाभ हुआ है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले प्रत्येक 3 ऋणों में से 2 महिलाओं को मिलते हैं, जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये तक के आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन स्तंभों पर आधारित है, अर्थात, बैंकिंग से वंचितों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करना और वित्तपोषित न होने वालों को वित्तपोषित करना।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय कोच ने घोषित की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम

नई दिल्ली। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच पामेला कोनटी ने कहा है कि रुस के खिलाफ सोची में होने वाले अंडर-17 फुटबॉल मुकाबलों के लिए उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर दिया गया है। भारतीय टीम 11 से 17 अप्रैल के बीच होने वाले इस दौर में रूस के खिलाफ तीन दोस्ताना मैच खेलेगी। इस दौरो के लिए 23 सदस्यीय टीम घोषित की गयी है। इस दौरे से भारतीय टीम को एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारी का भी अवसर मिलेगा। इस दौरे से खिलाड़ियों को अपनी रणनीति और तैयारियों को आंकने का अवसर मिलेगा। रूस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने से टीम अपने कमजोरियों को दूर कर सकेगी।

भारत और रूस के बीच ये तीनों मैच 11, 14 और 17 अप्रैल को सोची के मात्सेस्टा फुटबॉल सेंटर में होंगे। भारतीय टीम ने इन मुकाबलों के लिए सोची में अभ्यास भी शुरु कर दिया है। इस सीरीज से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल होगा। इस टूर्नामेंट से भारतीय टीम को इस साल चीन में होने वाले एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारी को अवसर मिलेगा।

गोलकीपर: मुन्नी, सूरजमुनी कुमारी, तम्फसाना देवी।

डिफेंडर: अलीना देवी, अलीशा लिंगदोह, दिव्यानी लिंडा, एलिजाबेद लाकड़ा, जॉयशिनी चानू, रितु बड़ाईक, तानिया देवी।

मिडफील्डर: अभिस्ता बासनेट, अल्वा देवी, बोनिफिलिया शुल्लई, जुलान नोंगमैथेम, प्रितिका बर्मन, रेडिमा देवी, थंडामोनी बास्की।

फॉरवर्ड: अनुष्का कुमारी, अनविता रघुरामन, जोया, ओलिविया चानू, पर्ल फर्नांडीस, वैलैना फर्नांडीस।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 2947 अंक दौड़ निफ्टी 23997 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार (8 अप्रैल) को जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा से दुनिया भर के शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त लेकर 77,290 पर खुला। जबकि मंगलवार को यह 74,616 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 77,635 अंक तक चढ़ गया था। अंत में यह 2946.32 अंक या 3.95 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 77,562.90 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 (निफ़्टी-50) भी बड़े उछाल के साथ 23,855 अंक पर खुला। एक दिन पहले यह 23,121 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 24,025 अंक के हाई तक गया। अंत में 873.70 अंक या 3.78 फीसदी की जोरदार तेजी लेकर 23,997.35 पर बंद हुआ।

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया कि वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद और गति मजबूत बनी हुई है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद लिए गए इस फैसले ने बाजारों को स्थिरता और निरंतरता का स्पष्ट संकेत दिया है। मल्होत्रा ने अपने बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है।

खुदरा मुदास्फीति के चालू वित्त वर्ष में 4.6% रहने का अनुमान

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में खुदरा महंगाई दर 4.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। यह आरबीआई के संतोषजनक दायरे के अंदर हैं। सरकार ने केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत के वृहद आर्थिक बुनियादी तत्व मजबूत दिख रहे थे और आर्थिक वृद्धि दर बेहतर एवं महंगाई कम रहने का आकलन किया जा रहा था। हालांकि, पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करते हुए बुधवार को कहा कि अप्रैल-जून की पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर चार प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सीजफायर और होर्मुज खुलने से निर्यातकों को राहत

नईदिल्ली। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने बुधवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के साथ-साथ अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा से निर्यातकों को तत्काल राहत मिलेगी और पोत परिवहन मार्ग के व्यवधान कम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को दो सप्ताह के लिए रोकने की घोषणा की। ईरान ने युद्धविराम के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से सुरक्षित नौवहन की अनुमति देने पर सहमति जताई, जिससे तेल, शेयर बाजार और मुद्रा बाजार में तेजी से बदलाव आया। फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा, युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य का फिर से खुलना निर्यातकों को शिपिंग बाधाओं, उच्च ढुलाई दरों और बीमा लागत में राहत देता है।

सही कदम है आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को रोकना

प्रो. अश्विनी महाजन

वर्ष 1991 में नयी आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से, जिसमें तीन मुख्य आयाम शामिल थे- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण- बैंकों के निजीकरण का मुद्दा हमेशा ही एक विवादास्पद विषय रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश दो तरीकों से होता है- रणनीतिक बिक्री से और बाजार आधारित शेयर बिक्री से। रणनीतिक बिक्री में अक्सर मूल्यांकन से जुड़ी समस्याएं, बोली लगाने वालों की सीमित संख्या और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आते हैं। इसके विपरीत, शेयर बाजार के जरिये किया जाने वाला विनिवेश अधिक पारदर्शी होता है, इसमें अधिक लोगों की भागीदारी होती है और इससे शेयरों का सही मूल्य तय हो पाता है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी संस्थाओं को बेचने का कोई इतिहास नहीं रहा है। फिर भी, अलग-अलग बैंकों के विलय के जरिये बैंकों की कुल संख्या में निश्चित रूप से कमी आयी है। जहां कुछ समय पहले तक सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर मात्र 12 रह गयी है। इसके अतिरिक्त, एक और बैंक है, जिसका नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आइडीबीआइ) है, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरहोल्डिंग मिलाकर सरकार का कुल नियंत्रण लगभग 95 प्रतिशत हो जाता है। विशेष रूप से आइडीबीआइ बैंक के मामले में, पिछले कुछ वर्षों से सरकार रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, और इस संबंध में पहले प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अब इस बैंक के रणनीतिक विनिवेश को रोक दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण तर्क दिये जाते रहे हैं। पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के आलोचकों के, खासकर आइडीबीआइ के मामले में, अपने मजबूत तर्क हैं। आइडीबीआइ बैंक, जो कुछ वर्ष पहले एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, अब घाटे से उबर चुका है और एक मुनाफा कमाने वाली संस्था बन गया है।

हालांकि, इसके निजीकरण के समर्थकों का पहला तर्क यह है कि आइडीबीआइ के निजीकरण से बाजार अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और पूंजी का कुशल आवंटन होगा। दूसरा, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नौकरशाही की देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। तीसरा, निजीकरण से परिसंपत्ति की गुणवत्ता और एनपीए के प्रबंधन में सुधार हो सकता है। चौथा, निजीकरण बैंकिंग सेवाओं में नवाचार, ग्राहक केंद्रित उत्पादों और डिजिटल बदलाव के जरिये प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। पांचवां, निजीकरण प्रबंधन बोर्ड की अधिक मजबूत जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन मानकों के जरिये कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार कर सकता है। छठा, भारत सरकार ने आइडीबीआइ बैंक को चालू रखने के लिए उसमें बार-बार पूंजी डाली है। निजीकरण करदाताओं के पैसे पर बार-बार होने वाले पूंजीकरण को कम करने में मदद कर सकता है। भारत और दुनियाभर में निजी क्षेत्र के बैंकों के दिवालिया होने का एक इतिहास रहा है। लेकिन, ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक दिवालिया हुआ हो और जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया हो। दूसरी बात, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लोगों का भरोसा आम जनता को अपनी बचत इन बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब 1969 में पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में छह और बैंकों का, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। यह देखते हुए कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, शिक्षा, निर्यात को बढ़ावा देना आदि प्राथमिक महत्व के क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिये इन 'प्राथमिक क्षेत्रों' के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी। आरबीआइ के तमाम नियमों, उप नियमों और निर्देशों के बावजूद, निजी क्षेत्र के बैंक उस तरह से वित्तीय समावेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर रहे हैं।

वनोपज आधारित रोजगार को दें बढ़ावा: कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की व्यापक समीक्षा करते हुए डिजिटल मॉनिटरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। इस अवसर पर उन्होंने 'प्रेलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट (पीओआर)' प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी सहायता से वन अपराधों की निगरानी और कार्रवाई में पारदर्शिता एवं गति आएगी। बैठक में मंत्री कश्यप ने अफसरों से कहा कि बस्तर क्षेत्र जो माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो गया है वहां पर भी वन अमले की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

मंत्री कश्यप ने रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कूपों की कटाई कराने तथा अमले की आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक वनोपज पर आधारित रोजगार मूलक कार्य गतिविधियों को बढ़ाने की बात कही। साथ ही वन क्षेत्रों में लघु वनोपज का शत-प्रतिशत संग्रहण सुनिश्चित करने, इको टूरिज्म सहित रोजगारमूलक और प्रसंस्करण संबंधी कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

वन मंत्री कश्यप ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका असर जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने विभाग को रोजगार सृजन, वन आधारित उद्योगों के विस्तार और राज्य की पहचान मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं, विशेषकर कैम्पा कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट कहा कि अब योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए और हर पात्र हितग्राही तक समय पर लाभ पहुंचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सभी स्वीकृत कैम्पा कार्यों का 100 प्रतिशत व्यय सितंबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। किसी भी स्थिति में फंड लैप्स स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए लैंड बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। वहीं, वन्य प्राणी प्रबंधन योजना में गुणवत्ता सुधार, व्यय वृद्धि तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

नई गाइडलाइन

इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र नई गाइडलाइन जारी करने तथा पीपीपी मॉडल के माध्यम से पर्यटन को गति देने पर बल दिया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें उचित मूल्य एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मंत्री कश्यप ने वृक्षारोपण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को प्रभावी बनाने तथा 'जी राम योजना' के अंतर्गत नर्सरियों में बड़े पौधे तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे अधिकाधिक पौध वितरण संभव हो सके।

कार्रवाई के निर्देश

बैठक में वन मंत्री कश्यप ने अवैध शिकार, अवैध कटाई एवं अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। साथ ही ग्रीष्मकाल में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए फील्ड स्टाफ की सक्रियता बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, वन अधिकार पत्रों के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र हितग्राहियों को ही लाभ देने पर विशेष बल दिया गया। वन्य प्राणियों से जनहानि के मामलों में त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

छात्रा मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा

4एस मॉडल पर रायपुर छात्रा संसद में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का संदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुराना विधानसभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में एबीवीपी द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि यदि छात्रा मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। छात्रा संसद का पूरा फोकस 4 एस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वालंबन और सुरक्षा पर रहा। छात्रा संसद को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केवल जागरूक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस जागरूकता को सही दिशा देना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही यदि युवतियां जिम्मेदारी लेंगी, तो विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार किया जा सकेगा।

4एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वालंबन और सुरक्षा। इन 4 अहम स्तंभों पर कार्यक्रम में चर्चा हुई। प्रदेशभर से आई छात्राओं ने सर्वे के आधार पर बताया कि इन क्षेत्रों में महिलाओं और छात्राओं के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें अवसर में कैसे बदला जा सकता है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि भारत में नारी सम्मान की परंपरा रही है, लेकिन इसे सामाजिक व्यवहार में और मजबूती से उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के जरिए जमीन पर मजबूत होगा।

यह मंच छात्राओं को सीखने, बोलने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा से भविष्य के नेतृत्व की पहचान होती है।- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एबीवीपी की प्रांत छात्रा प्रमुख राशि त्रिवेदी ने कहा कि कई वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में इतने बड़े स्तर पर छात्रा संसद का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया से पहुंचीं छात्राओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों को सामने रखा, ताकि छात्र नेतृत्व को सकारात्मक दिशा दी जा सके।

मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन होगा तेज

रायपुर। राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की अहम संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला से लेकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में भूपेश बघेल, टी। एस। सिंहदेव और चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संगठन विस्तार, मनरेगा आंदोलन की समीक्षा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया इस बैठक के केंद्र में रही।

बैठक में जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ कमेटियों के गठन की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक-एक जिले की कार्यकारिणी की स्थिति पर फीडबैक लिया और जिन जिलों में बूथ कमेटियां अधूरी हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर गठन पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। पंचायत, विलेज और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर पार्टी का फोकस रहा।

बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदेशभर में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्षों के पिछले 4 महीनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा गया। जिला स्तरीय जन मुद्दों, स्थानीय आंदोलनों और भाजपा सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। साफ संकेत दिया गया कि कांग्रेस अब गांव, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा। बैठक में पहला प्रस्ताव असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्राचार्यों की राज्य स्तरीय बैठक आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्राचार्यों की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन 9 अप्रैल 2026 को दोपहर बजे पं. दीनदयाल ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर में किया जाएगा। यह बैठक स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें राज्यभर के लगभग 751 विद्यालयों के प्राचार्य भाग लेंगे।

बैठक में आगामी शिक्षा सत्रं के बोर्ड परीक्षा परिणामों के लक्ष्य निर्धारण, नीट एवं जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की भागीदारी और सफलता बढ़ाने की रणनीति, प्रवेश प्रक्रिया, अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार के प्रयास, पीटीए बैठकों की समीक्षा, पालक-अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार सह-शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धियां, विद्यालयों के आकर्षक शैक्षणिक वातावरण निर्माण, स्मार्ट क्लास एवं पुस्तकालय के उपयोग, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार तथा नवाचार गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी संबंधित प्राचार्यों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सड़क पर रेत-गिट्टी बिखेरने वालों पर रायपुर कलेक्टर का एक्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क को निजी गोदाम समझने वालों पर अब प्रशासन का सख्त प्रहार शुरू हो गया है। शहर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ। गौरव सिंह जब चंगोराभाठा और डीडी नगर पहुंचे, तो सड़कों पर फैली निर्माण सामग्री देखकर भड़के। आम लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक में बाधा बन रही इस लापरवाही पर कलेक्टर ने मौके पर ही जब्ती और जुर्माने का आदेश दे दिया।

रायपुर के चंगोराभाठा और डीडी नगर का कलेक्टर ने जायजा लिया पैदल निकले कलेक्टर, गलियों में दिखी अव्यवस्था, जोन क्रमांक-5 के डगनिया और चंगोराभाठा क्षेत्र में कलेक्टर ने खुद पैदल चलकर गलियों और सड़कों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई निर्माणाधीन भवनों के बाहर सड़क तक फैली रेत, गिट्टी और ईंटें मिलीं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था, बल्कि राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ रहा था। इसे देखकर कलेक्टर ने तत्काल नाराजगी जताई।

कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर रखी निर्माण सामग्री तुरंत जब्त की जाए। साथ ही संबंधित मकान मालिक और ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सामग्री को व्यवस्थित तरीके से किनारे रखना अनिवार्य है, सड़क पर फैलाकर आम जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

डॉ. गौरव सिंह ने दो टूक कहा कि सड़क पर निर्माण सामग्री रखने से यातायात बाधित होता है और हादसों की आशंका बढ़ती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सरकार बताये कितने उर्वरक की डिमांड है: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खरीफ सीजन आने वाला है। सरकार ने अभी तक उर्वरकों की व्यवस्था के बारे में निश्चिंत बनी हुई है। अभी तक सरकार को किसानों की जरूरत के अनुसार सोसायटियों से मांग का डाटा एकत्रित कर सभी सोसायटियों में खाद पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार बताये कि इस वर्ष कितने उर्वरकों की

जरूरत का आंकलन किया गया तथा सरकार के पास कितनी उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को 14 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता थी, साय सरकार शुरू के दो माह तक मात्र 80 हजार मीट्रिक टन ही उर्वरक दे पायी थी, आखिर तक जरूरत से आधे का भी इंतजाम नहीं कर पायी सरकार। किसान यूरिया से लेकर डीएपी और पोटाश सभी के लिए भटकते रहे, बिचौलियों के द्वारा ब्लेक मार्केट में तीन से चार गुने दाम में किसानों को यूरिया और डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ा था। किसान खरीफ सीजन शुरू होने के तीन महिना पहले फरवरी में ही अपनी डिमांड सोसायटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देते है।

नियमितीकरण के अपने वायदों से मुकर गई है सरकार: शुक्ला

रायपुर। दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी उच्च न्यायालय में एक बार फिर उजागर हुई है। 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था सवा दो साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारी संवैधानिक नियोक्ता है और गरीब

कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती। जो लोग बुनियादी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को संभाल रहे हैं उनके हित में सहानुभूति पूर्वक विचार कर चार महीने के भीतर निर्णय लेने के कठोर निर्देश जारी किया गया है। भाजपा सरकार की नीयत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और इसीलिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने का कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार हर विभाग में कर रही है। भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग को ठगा है पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू किया नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के हक का काटा गया।

सत्ता की आड़ में सट्टा चला रहे हैं भाजपाई: वर्मा

रायपुर। सत्ता के संरक्षण में सट्टा का अवैध कारोबार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार में महादेव सट्टा सहित दर्जनों गेमिंग ऐप का विस्तार हुआ है। विगत 2 वर्षों में महादेव सिंडिकेट में कई ऑनलाइन सट्टा पैनल सक्रिय हैं। इनमें रेड्डी अन्ना, रेड्डी क्लब, ऑनलाइन बुक, बेटभाई बुक, फेयरप्ले, सुपरविन, विनबज, जन्नत बुक, महाकाल बुक, राजवीर ऑनलाइन बुक, लोटस 365, लेजर बुक, कोहनूर बुक, अलीबाबा बुक, खेलोयार, एसडी बुक, लॉयन बुक,

स्काईएक्सचेंज और डायमंडएक्स डॉट कॉम जैसे दर्जनों नए नए सट्टा ऐप खुलेआम चल रहे हैं इस सरकार में। ऑनलाइन गेमिंग ऐप केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग से नियंत्रित होती है लेकिन महादेव सट्टा कांड के तार पीएमओ से लेकर लॉ कमीशन और प्रसार भारती तक के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे। पीएमओ के अधिकारी और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हिरेन जोशी, हितेश शाह और प्रसार भारती के नवनीत शहगल जैसे लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेहद स्पष्ट है कि सत्ता के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में महादेव सट्टा एप खुले आम देशभर में चल रहा है।

अब योग की छुट्टी दे रहे : वंदना राजपूत

रायपुर। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को ध्यान योग शिविर के लिये 12 दिन के विशेष अवकाश पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि दो साल में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में सरकारी आफिसों में काम करने की संस्कृति समाप्त हो गयी है। सत्ता में बैठे हुये भाजपा के नेताओं द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों पर गैर कानून और अनैतिक काम करने के लिये इतना दबाव डाला जाता है कि कर्मचारी नियमित काम करने से भी डरने लगे है। उनके ऊपर डाले जा रहे अनैतिक काम के बोझ के कारण उनमें

तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा है। सरकार अपने हुक्मरानों का व्यवहार सुधारने के बजाय कर्मचारियों को योग करने की छुट्टी देने का निर्णय ले रही है। सरकार बताये कि क्या उसने कोई सर्वे किया है किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कर्मचारी को एक बार में 12 दिन का योग अवकाश दिया जायेगा। कर्मचारी पूरे सेवाकाल में 6 बार इस प्रकार का अवकाश ले सकते है। उन्हें इस छुट्टी के दौरान योग केन्द्रो और विपश्यना केन्द्रो से शिविर में शामिल होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। क्या प्रदेश में इतने विपश्यना केन्द्र है, कि वे सभी सरकारी कर्मचारियों को ध्यान योग की सेवाएं दे पायेगे।

छत्तीसगढ़ कॉमन्स कंवीनिंग 9 अप्रैल से नवा रायपुर में

रायपुर। साझा प्राकृतिक संसाधनों (कॉमन्स) के सुशासन और सामुदायिक संरक्षण पर केंद्रित दो दिवसीय छत्तीसगढ़ कॉमन्स कंवीनिंग का आयोजन 9 एवं 10 अप्रैल को सबेरे 10:30 बजे से ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24, नवा रायपुर में किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स पहल के अंतर्गत विभिन्न साझेदार संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में नीति-निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक प्रतिनिधि, शोधकर्ता एवं मीडिया से जुड़े लोग भाग लेकर कॉमन्स के सुशासन, सामुदायिक प्रबंधन और संस्थागत तंत्र पर विचार-विमर्श करेंगे। 9 अप्रैल को उद्घाटन सत्र में प्रमुख सचिवसोनमणि बोरा कॉमन्स विषय पर मुख्य वक्तव्य देंगे, जबकि 10 अप्रैल को मुख्य सचिव विकास शील जनजातीय नीति पर संवाद में शामिल होंगे। समापन सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। सम्मेलन में पद्मश्री सम्मानित पांडी राम मांडवी एवं जोगेश्वर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री अश्विनी कंगे और इंदु नेताम, पर्यावरणविद् रामवीर तंवर सहित कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम में कॉमन्स का सुशासन, जलवायु परिवर्तन, आजीविका, सामुदायिक संरक्षण, सांस्कृतिक आयाम और नीति समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन

मोर गांव-मोर पानी, मोर तिरिया अभियान बना जनभागीदारी का मॉडल

रायपुर। विष्णु देव साय सरकार के निर्देश पर आज प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चावल महोत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व ही विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों एवं समस्याओं का निराकरण कर योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मोर गांव - मोर पानी - मोर तरिया अभियान के अंतर्गत नवा तरिया ङ्क आय के जरिया पहल ने जनभागीदारी का सशक्त उदाहरण पेश किया। युवाओं एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से जल संरक्षण हेतु नवा तरिया निर्माण के लिए स्थलों की पहचान की और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने की ठोस कार्ययोजना तैयार हुई।

मनरेगा के तहत कार्यों में तेजी लाते हुए प्रगतिरत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा मांग आधारित नए कार्य प्रारंभ करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही आजीविका डबरी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि हेतु के लिए योजनाओं पर भी लोगों को जानकारी दी गई।

इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवासों को अधिकतम 90 दिवस में पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। साथ ही हितग्राहियों को प्राप्त राशि की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने एवं लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यक्रम में स्व-सहायता समूह की दीदियों की भूमिका को सशक्त करते हुए उन्हें सामग्री आपूर्ति एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नागरिक सूचना पटल पर समूह से जुड़े परिवारों की महिलाओं का नाम अंकित कर पारदर्शिता एवं सम्मान सुनिश्चित किया गया है। तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए त्तक्र कोड के माध्यम से मनरेगा एवं क्करूड्ड-त्न कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। अमृत सरोवरों एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर भी त्तक्र कोड आधारित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की ओर से कहा गया है कि इस सुविधा का लोग लाभ उठाएं

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा स्लोगन, नारे एवं जिंगल के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

देश की आधी आबादी को अनदेखी करना सरकार का तानाशाही रवैय्या: उत्तम

रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी डिजिटल जनगणना और 1 मई से 30 मई भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित 33 बिंदुओं में अन्य ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार ओबीसी वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है।मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 52% बताई गयी थी और सर्वेक्षण (ICE 360, 2021) के अनुसार भारत की अनुमानित 141 करोड़ की आबादी में, लगभग 44%-48% आबादी यानि की 62-68 करोड़ लोग ओबीसी समूह से आतें हैं। देश की आधी आबादी की अनदेखी समझ से परे है? पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नज़र आ रही है, क्या पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। समाज के साथ अन्याय है। बिना पृथक कॉलम के ओबीसी वर्ग की सही संख्या कैसे सामने आएगी? पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखने की सरकार की साजिश है। वहीं आठवीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 के 33 बिंदु वाले कालम में ओबीसी वर्ग की पृथक उल्लेख नहीं होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एससी एसटी ओबीसी महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज में इस जनगणना के प्रति कितना रोष है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.